सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 130, नई दिल्ली, शनिवार 19 जुलाई 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।

03 वीरेंद्र सचदेवा ने 15वें कांवड़ शिविर का शुभारंभ किया

06 परीक्षा प्रणाली या सामाजिक भ्रमजाल?

08 न्यायिक विभागीय जाँच होने तक आंदोलन जारी रहेगा। : संयुक्त विपक्ष

दिल्ली में सार्वजनिक सवारी सेवा और भी चरमराई, आखिर कौन है जिम्मेदार ?

पिंकी कुंडू सह संपादक परिवहन विशेष

नई दिल्ली। दिल्ली भारत देश की राजधानी जहां सार्वजनिक सवारी सेवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्ध होनी चाहिए पर पूर्व में रही आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक सवारी सेवा के लिए अपने पूरे कार्यकाल में एक भी बस ना तो खरीद कर दी और ना ही दिल्ली को सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाने वाले दिल्ली परिवहन निगम को खरीदने दी। कारण जो भी रहा हो पर दिल्ली में जनता को सुरक्षित, समयानुसार सेवा से वंचित कर दिया। दिल्ली में पूर्व से जनता को सुरक्षित समयानुसार सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली की सड़को पर प्राइवेट स्टेज कैरीज परमिट बसे (ब्लू लाइन), मिनी बस में आर टी वी और मेट्रो फीडर के साथ दिल्ली परिवहन निगम की बसे चलती थी। बाद मे जनता को सुरक्षित समयानुसार सार्वजनिक सेवा के लिए दिल्ली में ब्लू लाइन की जगह कलस्टर बसे, मिनी बस में आर टी वी और मेट्रो फीडर के साथ दिल्ली परिवहन निगम की बसे चलती रही।

आज की तारीख़ में दिल्ली में जनता को सुरक्षित समयानुसार सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाने के लिए ना तो कलस्टर बसे, ना ही मिनी बस में आर टी वी और मेट्रो फीडर और ना ही दिल्ली परिवहन निगम की बसे चलती है।

अब आप स्वयं फैसला करे की दिल्ली की जनता को सुरक्षित समयानुसार सार्वजनिक सवारी सेवा कैसे प्राप्त हो सकती है और दिल्ली की जनता को मजबूर हो कर आखिर किसके कारण गैर कानूनी तरीके से चलने वाले वाहनों में सफर करने के लिए मजबूर कर रखा है।

दिल्ली में सार्वजनिक सवारी सेवा वाहनों में होने वाले महिला उत्पीड़न, लूटमार और जेब तराशी की बढ़ती घटनाओं का जिम्मेदार कौन, बड़ा सवाल ?

दिल्ली में गैर कानूनी) अवैध तरीके से वाहनों को चलवाने का जिम्मेदार कौन ?

क्या भारत की राजधानी में दिल्ली सरकार और भारत सरकार का मिश्रित दायित्व नहीं बनता की दिल्ली में 24 घंटे सार्वजनिक सवारी सेवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वह भी सुरक्षित और समयानुसार उपलब्ध रहे ?

ट्रक व ट्रकों से संबंधित सामान पर 28 प्रतिशत या इसके आस पास लगाया जा रहा है जीएसटी...

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ट्रक व ट्रकों से संबंधित सामान पर 28% या इसके आस पास GST लगाया जा रहा है और GST रिटर्न भरने वाले लोग इस टैक्स का इनपुट (मतलब की टैक्स के रूप में भरी गयी इस राशि को वापसी) ले रहे हैं जिस कारण ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है क्योंकि जो ट्रक जिसकी अंदाजन कीमत 40 लाख रुपये है उसको सिर्फ़ खरीदने पर ही लगभग 10 लाख का GST लगता है और इसी 10 लाख का इनपुट या रिटर्न GST भरने वाले बड़े ट्रक मालिक ले लेते हैं और एक आम ट्रक मालिक को इस GST का कोई फायदा नही मिल पाता जिसके कारण जिस व्यक्ति को 40 लाख की गाड़ी 30 लाख में पड़ती है तो निश्चित है कि सिंगल ट्रक मालिक बाजार में टिके रहने के लिए उसका मुकाबला नही कर पाता जिस कारण छोटे ट्रक मालिक धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर हैं।

देश के सभी संगठनों की काफी समय से सरकार से अपील थी कि GST की इस विसंगति को दूर किया जाए ताकि एक आम ट्रक मालिक भी इस व्यवसाय से जुड़ा राह सके।

अब मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार जल्द ही ट्रक व्यवसाय से संबंधित GST के इस नियम में संशोधन करने का विचार कर रही है और GST दर 28% से घटा कर 18% लागू करने और GST के इनपुट को लेने वाले सिस्टम को बंद करने का विचार कर रही है जो कि स्वागत योग्य निर्णय है और अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रक व्यवसाय व छोटे ट्रक मालिको के हित के लिए सकारात्मक कदम होगा।

GST का इनपुट लेने वाले ट्रक मालिकों को भी इसका कोई खास फायदा नही हो रहा है क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण और GST का इनपुट लेने के लिए वो भी कम भाडो में काम करने को विवश हैं और जब वो भाड़े कम करते हैं तो एक आम ट्रक मालिक जिसको GST का इनपुट नही मिलता उसकी स्थिति तो चक्की में पीसने जैसी हो रही है। अतः सरकार को इस विषय पर विचार करते हुए GST के इनपुट सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए

राकेश अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता

हवाई यात्रियों से लेकर इंद्रलोक तक... हर इलाके में जाम से निजात दिलाने की दिल्ली सरकार ने की तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सरकार ने शहर में यातायात की समस्या को कम करने के लिए नौ बड़ी परियोजनाओं पर काम करने की योजना बनाई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इन परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया है जिसके लिए 19 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं में एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है जिससे हवाई अड्डे और अन्य क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा।

नईदिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार ने जनता को जाम ने निजात दिलाने के लिए ढांचा के विकास के मामले में कदम आगे बढ़ाते हुए नौ बड़ी परियोजनाओं को एक साल में जमीन पर उतार देने की योजना बनाई है। हवाई यात्रियों से लेकर इंद्रलोक तक हर इलाके में जाम से निजात दिलाने की तैयारी है।

सरकार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने तत्परता दिखाते हुए इन परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस कार्य पर 19 करोड़ की राशि खर्च करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। परियोजनाओं के लिए सड़कों के कुल 67 किलोमीटर भाग का व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा।

यह कार्य पूरा होने के साथ ही इन परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किया जाएगा, जिसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। यहां गौरतलब यह भी है कि दैनिक जागरण समय समय पर जाम वाले इन इलाकों का मुद्दा उठाता रहा है।

इन परियोजनाओं पर होना है काम

हरियाणा की मुनक नहर से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक एलिवेटेड कारिडोर के लिए सड़क के 20 किलोमीटर भाग का अध्ययन कराया जाएगा। इस कारिडोर विकास परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी यमुना नहर के किनारे एक एलिवेटेड कारिडोर का निर्माण करना है, जिसके साथ-साथ नहर के अग्र भाग को भी बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य भी किया जाएगा। यह विकास कार्य स्थानीय कला, संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा।

आइजीआई जाने वालों को राहत देने की तैयारी

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे जाने वाले लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, विभाग एनएसजी मुख्यालय के पास मुख्य पहुंच मार्ग और जंक्शन पर भीड़भाड़ कम करने की योजना बना रहा है। योजना में कहा गया है कि ₹यह निर्धारित करने के लिए 2 किलोमीटर सड़क भाग का एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा कि क्या अंडरपास, फ्लाईओवर या दोनों का निर्माण भीड़भाड़ कम करने के लिए किया जा सकता है। इस सड़क से दिल्ली, आइजीआइ हवाई अड्डे और गुरुग्राम जाने वाले यातायात का आवागमन होगा।

जाम मुक्त होगा नजफगढ़-फिरनी मार्ग

नजफगढ़-फिरनी मार्ग को पिछली आप सरकार ने प्रस्तावित किया था, मगर उस समय योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी। यह योजना फिर से अस्तित्व में आ गई है। इस कारिडोर पर, अध्ययन दो अलग-अलग सड़कों की भीड़भाड़ कम करने पर केंद्रित होगा: नजफगढ़-फिरनी रोड से एनएच-48 (कापसहेड़ा के पास) तक का क्षेत्र और पुरानी दिल्ली-गुड़ग्राम रोड का एक हिस्सा भी शामिल है। इस पूरे 20 किलोमीटर के हिस्से में कुल 15 ट्रैफ़िक सिग्नल हैं, जिनमें से अधिकांश प्रमुख चौराहों और उच्च जनसंख्या घनत्व या महत्वपूर्ण पैदल यात्री गतिविधि वाले क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं।

लोक निर्माण विभाग ने शिवाजी मार्ग पर ज़खीरा क्रॉसिंग से करमपुरा फ्लाईओवर तक 2.2 किलोमीटर लंबे हिस्से का अध्ययन करने का भी आदेश दिया है। यह हिस्सा पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर, कीर्ति नगर, पटेल नगर और करमपुरा इलाकों में यातायात की आवाजाही के लिए क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण है।

हिंद विहार के पास रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी)

दिल्ली-रोहतक रेलवे लाइन के ऊपर किराड़ी में हिंद विहार के पास सूखी नहर क्रासिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण, इसके तहत करीब 1 किमी इलाके में अध्ययन किया जाना है। मौजूदा सड़क जहां आरओबी का निर्माण प्रस्तावित है, यहां पर नांगलोई/रोहतक की ओर 25 मीटर का अधिकार क्षेत्र है जबकि रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर, सेक्टर 20-21, रोहिणी की ओर चौड़ाई केवल 12 मीटर है।

डीबी गुप्ता रोड परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन में हुआ बदलाव

पहाड़गंज इलाके से गुजरने वाले देश बंधु (डीबी) गुप्ता रोड पर प्रमुख लालबत्ती पर फ्लाईओवर बनाने की योजना है। इस परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में नया तथ्य यह जोड़ा गया है कि इस मार्ग पर पहले के 2 किलोमीटर भाग की जगह अब 7 किलोमीटर भाग का अध्ययन होगा। इसके अलावा सोनिया विहार एलिवेटेड कारिडोर के लिए 6 किलोमीटर भाग का अध्ययन, आइटीओ के लाला रामचरण अग्रवाल चौक पर फ्लाईओवर के लिए 4 किलोमीटर और इसी तरह शादीपुर डिपो चौराहे अंडरपास के लिए 4 किलोमीटर का अध्ययन इसमें शामिल है।

घरेलू सबज़ियाँ व लाभ

1 .करेला

अगर किसी व्यक्ति को पथरी की समस्या है तो उस व्यक्ति को करेला का सेवन जरूर करना चाहिए। करेला पथरी के उपचार में रामबाण काम करता है। इसमें मैग्नेशियम तथा फॉस्फोरस नामक तत्व पाए जाते है। और यह पथरी बनने से रोकता है। अतः करेला का सेवन अत्यंत लाभकारी होता है।

2 .परवल

जिस व्यक्ति को कब्ज गैस या अन्य पेट की बीमारी हो,तो परवल उसके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होती है। क्योकि परवल की सब्जी पचने में बहुत ही हल्की होती है। इसमें मौजूद रेशा लिवर और परवल में विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2 और विटामिन सी भरपूर मात्रा में

पाया जाता है।इसके अलावा ये कैल्शियम का भी अच्छा स्त्रोत है. इसके छिलकों में मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस भी भरपूर मात्रा में होता है। अतः परवल का सेवन करना भी अच्छा होता है।

3 .आलू

कभी -कभी हमे कुछ काम करते समय शरीर पर कही न कही चोट लग जाती है। और उस जगह पर नीला या काला पड़ जाता है।कच्चा आलू को उस स्थान पर पीस कर लगाने से बहुत ही जलद उस जगह से वह दाग मिट जाता है। क्योंकि आलू में आलू में सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक भी पाया जाता है।जिसके कारण दाग और धप्पा को बहुत जलद ख़त्म कर देता है।

4 .सिंघाणा

व्रत-उपवास सिंघाणा को फलाहार में शामिल किया जाता है। आयुर्वेदिक के अनुसार सिंघाणे में भैंस के दूध की तुलना में 22% अधिक खनिज लवण और क्षार तत्व पाए जाते है। अतः यह पैष्टिक तत्वों का खजाना है। इसमें कई औषधि गुण है,जिनसे शुगर ,हृदय रोग,अल्सर तथा गठिया रोग जैसे रोगो से बचाव होता है।

5 .लौकी

लौकी में एक अलग तरह की किस्म पाई जाती है। जिसमे से पोटैशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है,जिसकी वजह से यह गुर्दे के रोगो में बहुत उपयोगी है। इसके सेवन से पेशाब खुलकर आता है। तथा यह पेट के अल्सर में भी लाभदायक है।एक चम्मच हरे धनिया का रस,आधे निम्बू का रस तथा चुटकी भर सेंधा नमक आधे गिलास पानी में मिलकर रोगी को थोड़ी देर के अंतर पर पिलाने से उल्टी आनी बंद हो जाती है।

यह विशेष बात होगी जब हम दूसरों में छलकती करूणा को देख सकें। जो दूसरों में करूणा का दर्शन कर सकें वही अपने भीतर करूणा की तरंगों को विस्तृत/विस्तारित कर सकता है।

याद रहे कि हम वहीं दूसरों में देख पाते हैं जो हमारे भीतर कहीं गहरे में छिपा हो। देखने की हमारी दृष्टि/रिसेंबलेंस ही, दूसरों में बिल्कुल वैसे ही गुण-दोष खोज पाती है। इसीलिए हम अपने आदर्श के रूप में अपने कुल गुरु/ईष्ट/देवता को बड़े ध्यान से चुनें क्योंकि वह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भीतरी उन सोये बीजों को सींच सकतें हैं। सभी मनीषी अपने-अपने गुणों से भरपूर हैं लेकिन आज हम श्री गुरु नानक देवजी की बात करते हैं। जिसकी उनके प्रति श्रद्धा जाग जाये, वह भाग्यशाली है। संतों में संत-शिरोमणि नानक देवजी के प्रति श्रद्धा जागना, बड़े सौभाग्य की बात है। अनेक जन्मों से कोई व्यक्ति चित्त को निर्मल करते-करते संत बनता है। कोई चमत्कार से संत नहीं बन जाता। अनेक जन्मों से चित्त को निर्मल करते-करते, शांत करते-करते, वह संत हुए। उनकी बचपन की कहानी कहती हैं कि कभी पिता ने खेत की रखवाली के लिए भेज दिया, चिड़ियों के झुंड से बचाने के लिए। जाकर बैठ गये मचान पर। चिड़ियों के आने पर सोचते हैं कि 'अरे, इन बेचारियों को कहां भोजन मिलेगा?' जब वह दाना चुगने लगीं तो उनका मन बड़ा प्रसन्न होता है और प्रसन्नता में गाने लगतें हैं कि रहरि जी की चिड़िया, हरि जी का खेत। खा मेरी चिड़िया, भर भर पेट।।ह कितना गहरा प्यार। बचपन से ही कितना प्यार, कितनी मैत्री, कितनी करुणा, कितनी सद्भावना। जब किसी में मैत्री होती है, करुणा होती है तो उसकी तरंगें आसपास के वातावरण को भी मैत्री-करुणा से भर देतीं हैं। जहां भी ऐसी तरंगें आती हैं, उपज अपने आप ज्यादा होने लगतीं हैं। वास्तव में हमारी गई हुई करूणा/मैत्री कभी खाली नहीं रहतीं, लौट-लौटकर आतीं हैं और हमें भी द्विगुणित कर जातीं हैं। यदि हम उनके गुणों को आत्मसात करें, और अपने जीवन में उतारने/निखारने का प्रयत्न करें, तो हमारा कल्याण हो जाये।

त्रिपुरभैरवी स्तोत्र

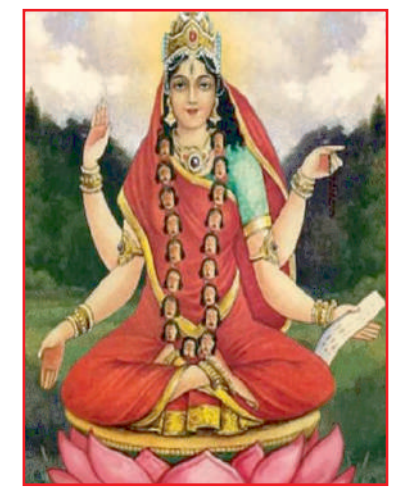

स्तुत्याऽनया त्वां त्रिपुरे स्तोष्येऽभीष्ट फलाप्तये।
यया व्रजन्ति तां लक्ष्मीं मनुजाः सुर पूजिताम्।।१
ब्रह्मादयः स्तुतिशतैरपि सूक्ष्मरूपां।
जानन्ति नैव जगदादिमनादिमूर्त्तिम्।
तस्माद्वयं कुचनतां नवकुंकुमाभां।
स्थूलां स्तुमः सकलवांगमयमातृभूताम्।।२
सद्यः समुद्यतसहस्त्रदिवाकराभां।
विद्याक्षसूत्रवरदाभयचिन्हहस्ताम्।
नेत्रोत्पलैस्त्रिभिरलंकृतवक्त्रपद्मां।
त्वां हारभाररुचिरां त्रिपुरे भजामः।।
सिन्दूरपूररुचिरं कुचभारनम्रं।
जन्मान्तरेषु कृतपुण्यफलैकगम्यम्।
अन्योन्यभेदकलहाकुलमानसास्ते।
जानन्तिं किं जडधियस्तव रूप मम्ब।।४
स्थूलां वदन्ति मुनयः श्रुतयो गृणन्ति।
सूक्ष्मां वदन्ति वचसामधिवासमन्ये।
त्वां मूलमाहुस्परे वचसामधिवासमन्ये।
मन्यामहे वयमपारकृपाम्बुराशिम्।।५
चन्द्रावतंसकलितां शरदिन्दुशुभ्रां।
पंचाशदक्षरमयीं हृदि भावयन्ति।
त्वां पुस्तकं जपवटीममृताढ्यकुम्भं।
व्याख्यांच हस्तकमलैर्दधतीं त्रिनेत्राम्।।६
शम्भुस्त्वमद्रितनया कलितार्द्धभागो।
विष्णुस्त्वमन्यकमलापरिबद्धदेहः।
पद्मोद्भवस्त्वमसि वागाधिवासभूमिः।
येषां क्रियाश्च जगति त्रिपुरे त्वमेव।।७
आकुंच्य वायुमवजित्य च वैरिषट्क।
मालोक्य निश्चलधियो निजनासिकाग्रम्।
ध्यायन्ति मूध्नि कलितेन्दुकलावतंसं।
तद्रूपमम्ब कृति तस्तरुणार्कमित्रम्।।८
त्वं प्राप्य मन्मथरिपोर्वपुरर्द्धभागं।
सृष्टिं करोषि जगतामिति वेदवादः।
सत्यं तदद्रितनये जगदेकमातः।
नोंचेदशेषजगतः स्थितिरेव न स्यात्।।९
पूजां विधाय कुसुमैः सुरपादपानां।
पीठे तवाम्ब कनकाचलगह्वरेषु।
गायन्ति सिद्धिवनिताः सह किन्नरीभिः।
रास्वादितामृतरसारुणपद्मनेत्रा।।१०
विद्युद्विलासवपुषं श्रियमुद्वहन्तीं।
यान्तीं स्ववासभवनाच्छिवराजधानीम्।
सौन्दर्यराशिकमलानि विकाशयन्तीं।
देवीं भजे हृदि परामृतसिक्तगात्राम्।।११
आनन्दजन्मभवनं भवनं श्रुतीनां।
चैतन्यमात्रतनुमम्ब तवाश्रयामि।
ब्रह्मेशविष्णुभिरुपासितपादपद्मां।
सौभाग्यजन्मवसतीं त्रिपुरे यथावत्।।१२
सर्व्वार्थभावि भुवनं सृजतीन्दुरूपा।
या तद्विर्भितत्त पुरनर्कतनुः स्वशक्त्या।
ब्रह्मात्मिका हरति तत्सकलं युगान्ते।
तां शारदां मनसि जातु न विस्मरामि।।१३
नारायणीति नरकार्णवतारिणीति।
गौरीति खेदशमनीति सरस्वतीति।
ज्ञानप्रदेति नयनत्रयभूषितेति।
त्वामद्विराजतनये विबुधा वदन्ति।।१४
ये स्तुवन्ति जगन्माता श्लोकैर्द्वादशभिः क्रमात्।
त्वामनुप्राप्य वाक्सिद्धिं प्राप्नुयुस्ते परां गतिम्।।१५
।।इति।।

भारत में समानता!? : मोदी सरकार के दावे का सच (आलेख : सवेरा, अनुवाद : संजय पराते)

मोदी सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने 5 जुलाई 2025 को एक बयान जारी कर विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत अब दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। इस बयान ने कॉर्पोरेट मीडिया में सरकार की नीतियों की प्रशंसा और जश्न का उन्माद पैदा कर दिया है। यह अजीब है कि अत्यधिक असमानता वाले देश में, जहाँ गरीबी और अभाव में जीने वाले लाखों लोगों के बीच अरबपति फल-फूल रहे हैं, सरकार और उसके समर्थक ऐसे दावों से लोगों और पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, इस सच्चाई को छिपाना अपराध है, क्योंकि इसका मतलब है कि मौजूदा असमानता, जो ब्रिटिश राज के दौर से भी आगे निकल गई है, को खत्म करने या कम करने के लिए अब कुछ नहीं किया जाएगा।

सरकार के इन दावों का आधार क्या है? आइए देखें कि यह धोखा कैसे फैलाया गया है।

गिनी सूचकांक : उपभोग व्यय बनाम आय

विश्व बैंक समय-समय पर विभिन्न विकास संकेतकों पर आँकड़े प्रकाशित करता है, जिनमें असमानता का एक मापक, जिसे गिनी सूचकांक कहा जाता है, शामिल होता है। यह सूचकांक 0 (पूर्ण समानता) और 100 (पूर्ण असमानता) के बीच होता है। इस सूचकांक की गणना का आधार देश में आय का वितरण है -- यानी, जनसंख्या का कितना हिस्सा कुल आय का कितना हिस्सा अर्जित करता है। इसलिए, गिनी सूचकांक के माध्यम से असमानता को मापने के लिए आय के आँकड़े आवश्यक हैं।

पश्चिम के अधिकांश उन्नत देशों में, आय के आँकड़े सीधे जनसंख्या के नमूनों के सर्वेक्षणों से एकत्र किए जाते हैं। लेकिन भारत जैसे अधिकांश विकासशील देशों में, आय सर्वेक्षण नहीं होते हैं। बहुत पहले, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (तब इसे एनएसएसओ कहा जाता था) ने यह निर्णय लिया था कि मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में घरेलू आय का निर्धारण करना कठिन है। इसलिए, उन्होंने उपभोग व्यय पर आँकड़े एकत्र करने का एक तरीका अपनाया। समय-समय पर, नमूना सर्वेक्षण किए जाते थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि परिवार हर महीने कितना खर्च (उपभोग व्यय) करते हैं। इसका उपयोग प्रातिनिधिक आय के विकल्प के रूप में किया जाता है।

यह कम आय वाले परिवारों के लिए कारगर है, क्योंकि उनकी अधिकांश आय खर्च हो जाती है और बचत लगभग नहीं के बराबर होती है। इसलिए, कमाई और खर्च के बीच का संबंध काफी हद तक सही है। हालाँकि, आबादी के अमीर तबके में, आय का केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही खर्च होता है। बाकी पैसा जमा कर लिया जाता है। अगर सर्वेक्षण में केवल घरेलू उपभोग व्यय के बारे में पूछा जाए, तो इससे अमीरों की आय का कम आकलन होता है।

असमानता पर विश्व बैंक के आँकड़े आय सर्वेक्षणों और उपभोग सर्वेक्षणों के बीच अंतर नहीं करते हैं, हालाँकि वे अपनी प्रस्तुति में इनके प्रकार का उल्लेख जरूर करते हैं।

मोदी सरकार द्वारा उद्धृत विश्व बैंक के हालिया आँकड़ों में विभिन्न देशों की सूची उनके संबंधित गिनी सूचकांकों के साथ दी गई है। यह दर्शाता है कि 2022 में भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ, पूर्व एनएसएसओ का नया नाम) द्वारा किए गए 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है।

अप्रैल 2025 में, विश्व बैंक ने एक 'गरीबी और समता : संक्षिप्त विवरण' जारी किया है, जिसमें इन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि ये उपभोग आधारित हैं। इसने इसकी तुलना अन्य देशों से नहीं की, क्योंकि उनमें से कई देशों के पास आय सर्वेक्षण आधारित आंकड़े होंगे और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। वास्तव में, विश्व बैंक ने गिनी सूचकांक के बारे में अपनी व्याख्या में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित कहा है :

'चूँकि अंतर्निहित घरेलू सर्वेक्षणों में एकत्रित कल्याणकारी उपायों के तरीकों और प्रकारों में भिन्नता होती है, इसलिए आँकड़े विभिन्न देशों में या किसी देश के भीतर विभिन्न वर्षों में भी कड़ाई से तुलनीय नहीं होते हैं। विशेष रूप से आय के वितरण के लिए गैर-तुलनीयता के दो स्रोतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला, सर्वेक्षण कई मामलों में भिन्न हो सकते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि वे जीवन स्तर के सूचक के रूप में आय का उपयोग करते हैं या उपभोग व्यय का। आय का वितरण आमतौर पर उपभोग के वितरण की तुलना में अधिक असमान होता है। इसके अतिरिक्त, सर्वेक्षणों में प्रयुक्त आय की परिभाषाएँ भी प्रायः भिन्न होती हैं। उपभोग आमतौर पर एक बेहतर कल्याणकारी सूचक होता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। दूसरा, घरों का आकार (सदस्यों की संख्या) और सदस्यों के बीच आय के बँटवारे की सीमा भिन्न होती है, क्योंकि व्यक्ति, आयु और उपभोग आवश्यकताओं में भिन्नता होती हैं। इन मामलों में देशों के बीच का अंतर वितरण की तुलना में पूर्वाग्रही हो सकता है। विश्व बैंक के कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आँकड़े यथासंभव तुलनीय हों।'

गिनी इंडेक्स की 2022 की डेटा श्रृंखला में भारत सहित केवल 61 देश शामिल हैं। इनमें से लगभग आधे देशों ने आय सर्वेक्षण किए हैं जबकि बाकी देशों ने उपभोग सर्वेक्षण किए हैं। चीन का डेटा उपभोग सर्वेक्षण पर आधारित है, लेकिन ब्राज़ील का डेटा आय-आधारित है। ज़्यादातर यूरोपीय देशों और अमेरिका के पास आय-आधारित डेटा है। 2011 में, जब भारत का गिनी इंडेक्स 28.8 आंका गया था, तब इस सूची में 82 देश शामिल थे। ये भी आय और उपभोग-आधारित डेटा का मिला-जुला समूह थे।

इस स्पष्ट सावधानी के बावजूद, जो गंभीर अर्थशास्त्रियों को भी अच्छी तरह पता है, मोदी सरकार ने बेशर्मी से अन्य देशों के साथ तुलना करके भारत को चौथा सबसे बड़ा समतावादी देश घोषित कर दिया है! यह और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि वास्तव में 2022 की गिनी सूचकांक सूची में केवल 61 देश हैं, और अन्य देशों के पास संभवतः उस वर्ष का प्रासंगिक डेटा नहीं है।

उपभोग के आँकड़े अमीर तबकों को कम आँकते हैं

उपभोग-आधारित आँकड़ों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि समाज का अमीर वर्ग - अरबपति और करोड़पति - सर्वेक्षण से वंचित रह जाते हैं। वे आबादी का एक छोटा-सा हिस्सा हैं और आमतौर पर घरेलू सर्वेक्षणों में कभी शामिल नहीं होते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई एनएसओ सर्वेक्षक मुंबई के एंटिला में मुकेश और नीता अंबानी से उनके मासिक खर्चों का पता लगाने के लिए उनके पास जाएगा? यह समस्या वैश्विक है, सिर्फ़ भारत तक सीमित नहीं है।

इसका नतीजा यह होता है कि अमीर परिवारों के उपभोग व्यय को ध्यान में नहीं रखा जाता और इस तरह उनके उपभोग के स्तर को बहुत कम करके आंका जाता है। भारत जैसे देशों में, जहाँ अधिकतम आय और संपत्ति आबादी के शीर्ष 1% लोगों में केंद्रित है, इसका मतलब है कि बाकी लोगों के उपभोग के स्तर में ज़्यादा अंतर नहीं है। इससे ज़्यादा 'समानता' का भ्रम पैदा होता है, जैसा कि कम गिनी सूचकांक में परिलक्षित होता है।

क्या इसका मतलब यह है कि अमीर लोगों के उपभोग, बल्कि उनकी आय, का अंदाज़ा लगाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, गंभीर अर्थशास्त्री और नीति-निर्माता जानते हैं कि इस कमी को काफी हद तक कैसे दूर किया जा सकता है। यह इस आलेख के अगले भाग में स्पष्ट हो जाएगा, जहाँ हम भारत में असमानता की वास्तविक स्थिति पर चर्चा करेंगे।

भारत में वास्तविक असमानता को कैसे मापा जाएं?

विश्व असमानता प्रयोगशाला के अर्थशास्त्रियों ने दर्शाया है कि भारत में आय और संपत्ति की असमानता अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, और मोदी शासन में इसमें और तेज़ी देखी गई है। पिछले साल प्रकाशित एक शोधपत्र में, उन्होंने निम्नलिखित आँकड़े दिए हैं :

'कुल आय में से, सबसे गरीब 50% आबादी को केवल 15% मिलता है, जबकि सबसे अमीर 10% आबादी 57.7% हड़प लेती है। देश की लगभग एक-चौथाई आय केवल शीर्ष 1% आबादी के पास है।'

इससे यह स्पष्ट है कि सबसे अमीर और सबसे गरीब लोगों के बीच आय में भारी अंतर है। यह बात वयस्क आबादी के प्रत्येक वर्ग की औसत वार्षिक आय पर नज़र डालने पर और भी स्पष्ट हो जाती है :

'भारत की शीर्ष 1% आबादी निचले 50% आबादी से 75 गुना ज़्यादा कमाती है। दरअसल, सबसे अमीर 0.001% आबादी सबसे गरीब 50% आबादी से 2800 गुना ज़्यादा कमाती है।'

अर्थशास्त्री इन चौंकाने वाले आँकड़ों पर कैसे पहुँचे हैं? उन्होंने राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों, आयकर के सारणीबद्ध आँकड़ों और आय व उपभोग पर विभिन्न एनएसओ/एनएसएसओ सर्वेक्षणों का उपयोग किया है। एनएसओ के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षणों में अमीर वर्गों के छूटे हुए आंकड़ों की भरपाई के लिए, उन्होंने समाज के उच्च वर्ग की आय को दर्शाने के लिए आयकर आँकड़ों का उपयोग किया। उनकी कार्यप्रणाली पारदर्शी है और ऊपर दिए गए शोध पत्र में विस्तार से दी गई है। हालाँकि ये आँकड़े पूर्णतः सही नहीं हैं, लेकिन सरकार जो प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, उससे कहीं अधिक वास्तविकता के करीब हैं।

इसी शोधपत्र में लेखकों द्वारा धन असमानता की गणना के लिए एक समान कवायद की गई है। ध्यान दें कि धन एक संचयी आँकड़ा है, जबकि आय वह है, जो एक सीमित अवधि में अर्जित होती है। इसलिए, इसकी उत्पत्ति और इसके पोषण दोनों में अंतर है।

भारत में सबसे गरीब 50% लोगों के पास कुल संपत्ति का मात्र 6.4% है, जबकि सबसे अमीर 10% लोगों के पास 60% का चौंका देने वाला हिस्सा है। आय के मामले में, लेखकों ने प्रत्येक खंड के लिए औसत संपत्ति अनुमान प्रदान किए हैं :

'भारत में सबसे गरीब 50% लोगों के पास औसतन लगभग 1.7 लाख रुपये की संपत्ति है। सबसे अमीर 10% लोगों के पास लगभग 88 लाख रुपये की संपत्ति है और सबसे अमीर 0.001% लोगों के पास औसतन 2261 करोड़ रुपये हैं, जो कि सबसे गरीब 50% लोगों की संपत्ति से 1.3 लाख गुना अधिक है।'

ये आँकड़े राष्ट्रीय संपत्ति समुच्चय, एनएसओ के अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) और फोर्ब्स अरबपति रैंकिंग का उपयोग करके अनुमानित किए गए हैं। उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में असमानता व्यापक और गहरी है।

कुछ अन्य देशों के साथ तुलना

चूँकि सर्वेक्षण में समान कार्यप्रणाली लागू की गई है और अंतरों को समायोजित किया गया है, इसलिए भारत की असमानता की तुलना अन्य देशों से करना संभव है। इसके लिए, लेखक कुछ अन्य देशों के आँकड़ों के लिए विश्व असमानता डेटाबेस का उपयोग करते हैं।

आय असमानता के मामले में, दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। दक्षिण अफ्रीका में शीर्ष 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 65% से अधिक हिस्सा हड़प लेती है, जो अत्यधिक असमानता को दर्शाता है। भारत में, यह हिस्सा लगभग 58% है। यदि आय में शीर्ष 1% की हिस्सेदारी पर नज़र डालें, तो दक्षिण अफ्रीका से भी आगे भारत दिखता है। भारत में राष्ट्रीय आय का लगभग 23% हिस्सा सबसे अमीर 1% लोगों को मिलता है। ये उस बेशर्म और भयावह असमानता के स्पष्ट संकेत हैं, जिसे सरकार छिपाने की कोशिश करती दिख रही है।

धन के संकेंद्रण के मामले में, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लगभग 86% धन का संकेंद्रण केवल 10% लोगों के हाथ में है। उसके बाद ब्राज़ील, अमेरिका और चीन और फिर भारत का स्थान है। भारत में शीर्ष 10% लोगों के पास 65% धन संकेंद्रित है।

इस प्रकार, मोदी सरकार का चौथा सबसे आर्थिक समानतावादी देश होने का दावा पूरी तरह से ग़लत है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि सरकारी प्रचार तंत्र चलाने वाले सभी चतुर लोग इतने भोले या मूर्ख हैं कि वे 61 देशों की सूची लेकर उसे 'विश्व' कहने और गिनी सूचकांकों से तुलना करने की गलती करते हैं, जबकि उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि मोदी सरकार को सच्चाई या वैधता की परवाह नहीं है -- उसे लगता है कि वह दिन को रात कह सकती है और बचकर निकल सकती है। यह वास्तविकता से पूरी तरह से अलगाव का लक्षण है और देश की जनता का अपमान भी है।

(लेखक आर्थिक टिप्पणीकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं)

रावण और कुबेर की कथा

रावण और कुबेर दोनों भाई थे तो फिर रावण असुर (राक्षस) और कुबेर सुर (देव) क्यों कहलाए?

पौराणिक संदर्भों के अनुसार पुलत्स्य ऋषि ब्रह्मा के दस मानसपुत्रों में से एक माने जाते हैं। इनकी गिनती सप्तऋषियों और प्रजापतियों में की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पुलत्स्य ऋषि को पुराणों का ज्ञान मनुष्यों में प्रसारित करने का आदेश दिया था। पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा ऋषि हुए, जो हविर्भू के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। विश्रवा ऋषि की एक पत्नी इलबिड़ा से कुबेर और कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए थे। सुमाली विश्रवा के श्वसुर व रावण के नाना थे। विश्रवा की एक पत्नी माया भी थी, जिससे खर, दूषण और त्रिशिरा पैदा हुए थे और जिनका उल्लेख तुलसी की रामचरितमानस में मिलता है।

दो पौराणिक संदर्भ रावण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जरूरी हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इंकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय-विजय को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय-विजय ने प्रार्थना की व अपराध के लिए क्षमा माँगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि तीन जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा।

यह शाप राक्षसराज, लंकापति, दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताललोक में पहुँचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वधकर पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्यकशिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्तकर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था।

भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करनेकी वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णुभक्त पुत्र प्रह्लाद को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था। खंभे से नृसिंह भगवान का प्रकट होना ईश्वर की शाश्वत, सर्वव्यापी उपस्थिति का ही प्रमाण है।

त्रेतायुग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब ये दोनों शिशुपाल व दंतवक्त्र नाम के अनाचारी

के रूप में पैदा हुए थे। इन दोनों का ही वध भगवान श्रीकृष्ण के हाथों हुआ।

त्रेतायुग में रावण के अत्याचारों से सर्वत्र त्राहि-त्राहि मची हुई थी। रावण का अत्यंत विकराल स्वरूप था और वह स्वभाव से क्रूर था। उसने सिद्धियों की प्राप्ति हेतु अनेक वर्षों तक तप किया और यहाँ तक कि उसने अपने सिर अग्नि में भेंट कर दिए। ब्रह्मा ने प्रसन्ना होकर रावण को वर दिया कि दैत्य, दानव, यक्ष, कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा, परंतु इसमें 'नर' और 'वानर' को शुमार नहीं किया गया था। इसलिए नर रूप में भगवान श्रीराम ने जन्म लिया, जिन्होंने वानरों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण तथा उसके कुल का विनाश हुआ।

प्रकांड पंडित एवं ज्ञाता होने के नाते रावण संभवतः यह जानता था कि श्रीराम के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। छल से वैदेही का हरण करने के बावजूद उसने सीता को महल की अपेक्षा अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि एक अप्सरा रंभा का शाप उसे हमेशा याद रहता था कि 'रावण, यदि कभी तुमने बलात्कार करने का प्रयास भी किया तो तुम्हारा सिर कट जाएगा।' खर, दूषण और त्रिशिरा की मृत्यु के बाद रावण को पूर्ण रूप से अवगत हो गया था कि वे 'मेरे जैसे बलशाली पुरुष थे, जिन्हें भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता था।

'रावण एक विचारक व दार्शनिक पुरुष था। वह आश्वस्त था कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भगवान हैं तो उनके हाथों मरकर उनके लोक में जाना उत्तम है और यदि वे मानव हैं तो उन्हें परास्त कर सांसारिक यश प्राप्त करना भी उचित है। अंततः रावण का परास्त होना इस बात काशाश्वत प्रमाण है कि बुराइयों के कितने ही सिर हों, कितने ही रूप हों, सत्य की सदैव विजय होती है। विजयादशमी को सत्य की असत्य पर विजय के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्रीराम ने त्रेतायुग में नवरात्रि का व्रत करने के बाद ही रावण का वध किया था।

पुलत्स्य ऋषि के उत्कृष्ट कुल में जन्म लेने के बावजूद रावण का पराभव और अधोगति के अनेक कारणों में मुख्य रूप से दैविक एवं मायिक कारणों का उल्लेख किया जाता है। दैविक एवं प्रारब्ध से संबंधित कारणों में उन शापों की चर्चा की जाती है जिनकी वजह से उन्हें राक्षस योनि में पैदा होना पड़ा। मायिक स्तर पर शक्तियों के दुरुपयोग ने उनके तपस्या से अर्जित ज्ञान को नष्ट कर दिया था।

ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद अशुद्ध, राक्षसी आचरण ने उन्हें पूरी तरह सराबोर कर दिया था और हनुमानजी को अपने समक्ष पाकर भी रावण उन्हें पहचाननहीं सका था कि ये उसके आराध्य देव शिव के अवतार हैं। रावण के अहंकारी स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि शक्तियों के नशे में चूर होने से विनाश का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्त के लिए विनयशील, अहंकाररहित होना प्राथमिक आवश्यकता है।

स्रोतः- पुराणों से

आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एवं आतिशी आदि नेता दिल्ली की सरकार खोने के बाद से पूरी तरह हताश हैं - 'वीरेन्द्र सचदेवा'

मुख्य संवाददाता/सुषमा रानी

नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की यह दुर्भाग्यपूर्ण है की जब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के आर्थिक अपराधों की जांच शुरू होती है या न्यायलय में सुनवाई आगे बढ़ने लगती है तो जांच या सुनवाई को राजनीतिक षडयंत्र बताने का उनका रटा रटाया अलाप शुरू हो जाता है।

पूर्व मुख्य मंत्री आतिशी मार्लेना का आज का ब्यान उनकी पार्टी की राजनीतिक खीझ का परिणाम है। चुनावी हार जीत लोकतंत्र का भाग है पर बिना संघर्ष अपने जन्म से सत्ता सुख भोगने वाली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल एवं आतिशी मार्लेना आदि नेता दिल्ली की सरकार खोने के बाद से पूरी तरह हताश हैं तथा आज तक हार के सदमे से उबर नही पा रहे हैं।

गत लगभग 5 साल से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एवं सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त रहे हैं और लम्बा समय जेल में रहने के बाद अब जमानत पर हैं। इनसे जुड़े सभी मामले अब न्यायिक जांच के दायरे में हैं, ₹आपद₹ नेता सार्वजनिक चर्चा में खुद पर लगे मामलों को राजनीतिक षडयंत्र बताते हैं पर

न्यायालय में यह मामले को फर्जी नही बताते वहां जमानत पर छूटने के लिए फरियादें करते दिखते हैं।

सचदेवा ने कहा की जैसे ही केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में ₹आपद₹ नेताओं के द्वारा अस्पताल निर्माण के दौरान किए घोटालों की जांच तेज़ हुई है तब से ₹आपद₹ नेताओं के रटे रटाये राजनीतिक अलाप प्रलाप तेज़ हो गये हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की अस्पताल निर्माण घोटाले की जांच भाजपा शासनकाल में ही शुरू हो गई थी पर राजनीतिक नौटंकी में परांगत ₹आपद₹ नेता अब उसे गुजरात की एक सीट की जीत से जोड़कर राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं।

आतिशी मार्लेना बतायें यदि भाजपा राजनीतिक प्रतिशोध में मुकदमें दायर कर कार्यवाई करती है तो फिर उन्हे किसी भी न्यायालय से राहत क्यों नही मिलती ?

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार ने राजधानी को हरा-भरा बनाने के लिए वन महोत्सव 2025 का आयोजन किया। राष्ट्रपति एस्टेट में हुए पौधारोपण कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की और 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य बताया। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने भी इस पहल की सराहना की।

नई दिल्ली। दिल्ल सरकार ने देश की राजधानी को हरित, पर्यावरण के अनुकूल व प्रदूषण से मुक्त करने के लिए बड़ी पहल की है।

राष्ट्रपति एस्टेट में शुक्रवार को आयोजित 'वन महोत्सव 2025' में जानी मानी हस्तियों ने दिल्ली सरकार की इस पहल की सराहना की है।

कहा कि ऐसे आयोजनों व जन-जागरूकता से ही दिल्ली सही मायनों में देश की राजधानी कहलाएगी। इस आयोजन के तहत राष्ट्रपति एस्टेट स्थित 11 विलिंगडन क्रिसेंट में एक विशेष पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की भावना को आत्मसात करते हुए,

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित सभी उपस्थित गणमान्य लोगों ने पौधारोपण किया।

इस अवसर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस नवीन चावला, जस्टिस ज्योति सिंह, जस्टिस अनूप भंभानी, जस्टिस अरुण त्यागी आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानीवासियों से अपील की, कि वे अपने घरों, आस-पड़ोस, विद्यालयों, कार्यालयों और सामुदायिक स्थलों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इस अभियान को एक जनांदोलन का रूप दें।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वन महोत्सव 2025 के तहत दिल्ली सरकार ने इस वर्ष 70 लाख से अधिक पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री ने पौधारोपण करते हुए दिल्लीवासियों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है।

मूवी रिव्यू 'मर्डरबाद' 'इमोशन, थ्रिल, मिस्ट्री का जबरदस्त तड़का क्लाइमेक्स आपको झकझोर देगा

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। यकीनन आप यह जानकर हैरान होंगे कि इस हफ्ते रिलीज हुई मर्डरबाद के निर्माता , निर्देशक , लेखक अर्नब चटर्जी ने अपनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर करीब 14 साल की उम्र ने काम शुरू किया और 18 साल के होने पर फिल्म की शूटिंग पिछले साल शुरू की , राजस्थान, वेस्ट बंगाल की कई आउटडोर लोकेशन पर शूट अपनी इस फिल्म के लिए साठ की उम्र पार कर चुके अंजन श्रीवास्तव , अमोल गुप्ते के साथ साथ अनुभवी एक्टर मनीष चौधरी को भी निर्देशित किया

इस फिल्म की मीडिया स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म का शो खत्म होने के बाद क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स लेने दिल्ली के लग्जरी डिलाइट डायमंड सिनेमा में अर्नब खास तौर से कोलकाता से दिल्ली आए उनका यहीं जुनून बताता है कि आने वाले दिनों में उनका नाम बॉलीवुड के नामी निर्देशकों की लिस्ट में शामिल होगा , यहां उनसे विशेष बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 8 साल की उम्र से ही शार्ट फिल्मे बनाने का ऐसा शिक्षा लगा कि मर्डरबाद जैसी फीचर बनाई , अर्नब कहते है मैने फिल्म को किसी स्टूडियो में सेट लगवाकर आराम से शूट करने की बजाय रियल लोकेशन पर शूट किया , राजस्थान के जयपुर शहर से यहां की कई आउटडोर लोकेशन और एक पैलेस के अलावा न्यू जलगपाई गुड्डी की कई लोकेशन पर शूट किया ।

स्टोरी प्लॉट

मेरी नजर में यह फिल्म आपको भयावह और कुछ वीभत्स दृश्यों को दिखाती है जिन्हें देखना आप

शायद पसंद नहीं करे लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड इन सींस की थी और यह स्टोरी का अहम हिस्सा बने।

प्रश्न से जकड़ लेता है, जयपुर के होटल में अलग अलग शहरों से आए टूरिस्ट का एक ग्रुप रुका हुआ है उनमें लंदन की टूरिस्ट भी शामिल है , गाइड और बस का ड्राइवर इन टूरिस्ट के साथ इसी होटल में रुका है अचानक एक टूरिस्ट यहां से गायब हो जाती है ₹ इस राजस्थानी महल में बने होटल की शांत लेकिन भयावह पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द घूमती यह कहानी मर्डर, पोस्टमार्टम हाउस के घिनौने सच और श्मशान से घूमती इस थ्रिलर फिल्म का क्लाइमेक्स आपको बेचैन कर देगा। होटल से गायब हुई एक टूरिस्ट के गायब होने की यह कहानी जल्दी ही रहस्यों और एक कुंठा ग्रसित युवक का वीभत्स चेहरा पेश करती है जो आपको चौंका देगा ।

ओवर ऑल

रोमांस इमोशनळ भावनाओं और रहस्य से भरी फिल्म की कहानी बाद में एक खतरनाक रूप में बदलकर एक ऐसी भूलभुलैया में प्रवेश करती है जहां से निकलना आसान नहीं है। निर्देशक अर्नब की कहानी और किरदारों पर फिल्म की शुरुआत में पकड़ कमजोर है लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म आपको सीट से बांध सी देती है, अर्नब ने मंझे हुए दिग्गज कलाकारो के साथ न्यू कमर्स स्टार्स से अच्छा काम लिया है, नकुल सहदेव और कनिका कपूर की जोड़ी जमी है लेकिन फिल्म नगरी में लंबी पारी खेलने के लिए इन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अर्नब की यह फिल्म क्लाइमेक्स के दौरान बांग्ला बैकग्राउंड में एंट्री करती है लेकिन फिल्म का अहम मोड है। फिल्म का क्लाईमेक्स हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे इसके लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा लेकिन फैमिली क्लास की कसौटी पर फिल्म फिट नहीं रहेगी लेकिन कुछ बिल्कुल नया और थ्रिलर देखने वाले दर्शक फिल्म को पसंद करेंगे

कलाकारः शाकिर हाशमी, नकुल रोशन सहदेव, कनिका कपूर, मनीष चौधरी, अमोल गुप्ते, मसूद अख्तर, सलोनी बत्रा,निर्माता, लेखक, निर्देशकः अर्नब चटर्जी, सेंसर सर्टिफिकेटः यू ए, अवधिः 143 मिनट

वीरेंद्र सचदेवा ने शकरपुर में श्री बालाजी सेवा संस्था (रजि.) द्वारा आयोजित 15वें कांवड़ शिविर का शुभारंभ किया

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज विकास मार्गशकरपुर में श्री बालाजी सेवा संस्था (रजि.) द्वारा आयोजित 15वें कांवड़ शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक श्री अभय वर्मा सहित शाहदरा जिला अध्यक्ष श्री दीपक गाबा सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य उपस्थित थे।

वीरेंद्र सचदेवा ने इस अवसर पर कांवड़ यात्रियों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना और शिवभक्ति से ओत-प्रोत वातावरण का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो हम सभी सनातनी मिलकर इसको पूरा करते हैं।

वीरेंद्र सचदेवा ने इस मौके पर कहा कि यह आयोजन न केवल सेवा का प्रतीक है, बल्कि समाज के प्रति हमारे दायित्व की भी स्मृति कराता है। इस बार की कांवड़ियों के लिए दिल्ली की श्रीमति रेखा गुप्ता की सरकार ने शानदार आयोजन किया है ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यह पहली बार दिल्ली में होगा जब लाखों कांवड़ियों के स्वागत के लिए दिल्ली में 17 भव्य द्वार बनाये गए हैं।

सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कांवड़ यात्रा को सफल, सुरक्षित और गरिमामय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि सामाजिक समरसता और सेवा भावना का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि शिविरों में साफ-सफाई, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, विश्राम, बिजली, मच्छर नियंत्रण, महिला सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है।

tसौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दैनिक जागरण अखबार अपनी इस गलती में सुधार करेगा।

पर्यटन को लेकर दिल्ली की ब्रांडिंग शुरू, हिमेश रेशमिया के साथ कपिल मिश्रा पहुंचे प्रधानमंत्री संग्रहालय

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने गायक हिमेश रेशमिया के साथ प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। उन्होंने संग्रहालय की विशेषताओं का अवलोकन किया और देशवासियों से दिल्ली के पर्यटन स्थलों पर आने की अपील की। मंत्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय युवाओं को प्रेरणा देने का एक माध्यम है। दिल्ली सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है।

नई दिल्ली। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की ब्रांडिंग के तहत पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रसिद्ध गायक एवं संगीत निर्देशक हिमेश रेशमिया के साथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया।

भ्रमण के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने संग्रहालय की विभिन्न तकनीकी विशेषताओं और गैलरियों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि आप सभी दिल्ली के इन पर्यटन स्थलों पर जरूर आएं।

प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित 14 अत्याधुनिक गैलरियां हैं, जो भारत के राजनीतिक इतिहास को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं।

संग्रहालय की विशेषताओं में 6D हेलिकॉप्टर राइड, इंटरैक्टिव जोन, वर्चुअल फोटो सेशन, हैंडराइटिंग रोबोट, टाइम मशीन, 3D नेशनल एम्बलम और काइनेटिक एलईडी लाइट्स से युक्त राष्ट्रीय ध्वज जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं।

इस अवसर पर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय न केवल हमारे देश के इतिहास को जीवंत करता है बल्कि यह युवाओं को प्रेरणा देने का भी एक माध्यम है।

यह भारत के महान नेताओं की यात्राओं और योगदान का सजीव दस्तावेज है। हर भारतीय को यहां आकर भारत के गौरवशाली नेतृत्व की झलक अवश्य देखनी चाहिए।

इसके साथ ही मंत्री मिश्रा ने अपने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि कर्तव्य पथ, भारत मंडपम, प्रधानमंत्री संग्रहालय, डा. अम्बेडकर स्मारक जैसे आधुनिक भारत की पहचान वाले पर्यटक स्थलों पर देशभर से लोग आएं।

इसी क्रम में आज मशहूर गायक हिमेश रेशमिया द्वारा किया औके साथ दिल्ली के प्रमुख टूरिज्म स्मारक प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाना हुआ।

देश की राजनीति, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता को दर्शाते ये नए पर्यटक स्थल दिल्ली की पहचान हैं। रेशमिया साथ प्रधानमंत्री संग्रहालय जाकर हमने इस अभियान की शुरुआत की है। आप सभी दिल्ली के इन पर्यटन स्थलों पर जरूर जाएं।

यमुना में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा फीकल कोलीफॉर्म, आईटीओ बैराज और आईएसबीटी पुल के पास हालात गंभीर

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है खासकर आईटीओ बैराज के पास जहाँ मल-मूत्र से होने वाले प्रदूषण की मात्रा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्षा के दिनों में गंदगी बहकर यमुना में पहुँचने से प्रदूषण बढ़ता है लेकिन इस बार की वृद्धि असामान्य है। विशेषज्ञों ने दिल्ली सरकार से इसकी जाँच कराने की मांग की है।

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद फरवरी से ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया था। नदी में गिरने वाले नालों की सफाई के साथ ही सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के अपग्रेडेशन का काम चल रहा है।

इसके बावजूद दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल समिति (डीपीसीसी) की रिपोर्ट के अनुसार मार्च की तुलना में जुलाई में यमुना में प्रदूषण बढ़ा है। सबसे खराब स्थिति आईटीओ बैराज के पास है।

मल-मूत्र से होने वाले प्रदूषण (फीकल कोलीफार्म) की मात्रा यहां रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। इससे विशेषज्ञ भी चिंतित हैं।

जनवरी और फरवरी की रिपोर्ट गुणवत्ता बेहद खराब

डीपीसीसी की जनवरी व फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार यमुना के पानी की गुणवत्ता बहुत अधिक खराब हो गई थी। फीकल कोलीफार्म का स्तर लगभग पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक था।

लेकिन, अप्रैल में स्थिति सुधर गई थी। पानी में फीकल कोलीफार्म का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर 500 सर्वाधिक संभावित संख्या (एमपीएन) होना चाहिए।

इसका स्तर 2500 एमपीएन पहुंचने पर यह उपयोग लायक नहीं रह जाता है। फरवरी में यह असगरपुर में 1.60 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन इस माह यह 7.9 लाख रह गया है।

विशेषज्ञ बोले- गंभीरता बरते सरकार

असगरपुर को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर यह बढ़ा है। आईटीओ बैराज के पास यह पहली बार 92 लाख पहुंच गया है। इससे पहले फरवरी में यहां सबसे अधिक 43 लाख और पिछले माह 35 लाख था।

विशेषज्ञों का कहना है कि वर्षा के दिनों में गंदगी बहकर यमुना में पहुंचने से यह मात्रा बढ़ती है, लेकिन इस तरह से असमान्य वृद्धि चिंताजनक है।

आईटीओ घाट पर कई तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। फीकल कोलीफार्म के साथ ही जैव रसायन ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और घुलनशील ऑक्सीजन (डीओ) की स्थिति की अभी भी चिंताजनक है।

स्वच्छ पानी में बीओडी तीन मिलीग्राम (एमजी) प्रति लीटर या इससे कम और डीओ पांच एमजी प्रति लीटर या इससे अधिक होना चाहिए। दिल्ली में कहीं भी इस मानक के अनुसार यमुना का पानी नहीं है।

आईटीओ बैराज के पास फेकल कोलीफार्म की स्थिति

- 25 जून 2024 को 24 लाख
- 29 जुलाई 2024 को 24 हजार
- 16 जून 2025 को 35 लाख

जब अमेरिका बोला भारत की भाषा: टीआरएफ पर वैश्विक प्रहार

[टीआरएफ का पर्दाफाश: आतंक की आड़ में पाकिस्तान]

22 अप्रैल 2025 की वह काली दोपहर, जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम की हरी-भरी वादियां खून से लाल हो गईं। बैसरन घाटी में घुड़सवारी का आनंद लेते, हंसी-ठिठोली करते पर्यटक एक पल में आतंक की भेंट चढ़ गए। आतंकवादियों ने पहले उनका धर्म पूछा, फिर क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए 26 बेगुनाहों को गोलियों से भून दिया। यह हमला, जिसकी जिम्मेदारी 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) ने ली, 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक आतंकी हमला था। इस नृशंसता ने न केवल भारत के दिल को चीर दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को और मुखर कर दिया। 17 जुलाई 2025 को अमेरिका ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) घोषित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो न सिर्फ भारत की कूटनीतिक जीत है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का प्रतीक भी है।

यह संगठन, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का छद्म चेहरा माना जाता है, 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उभरा। लश्कर-ए-तैयबा, जिसे संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, ने इस प्रॉक्सी का इस्तेमाल कश्मीर में हिंसा भड़काने और अंतरराष्ट्रीय जांच से बचने के लिए किया। भारतीय गृह मंत्रालय ने 2023 में इसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया था, यह बताते हुए कि इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाना, सुरक्षा बलों पर हमले करना और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंक की राह पर धकेलना है। लेकिन पहलगाम की घटना ने इस संगठन की क्रूरता को एक नई ऊंचाई दी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।

पहलगाम की त्रासदी ने मानवता को झकझोर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान रोंगटे खड़े करने वाले हैं— आतंकियों ने पीड़ितों से कलमा पढ़ने को कहा, फिर धर्म के आधार पर चुन-चुनकर हत्याएं कीं। मरने वालों में ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, जो कश्मीर की खूबसूरती में सुकून तलाशने आए थे। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इस संगठन ने न केवल अपनी बर्बरता का प्रदर्शन किया, बल्कि आतंक का प्रचार कर घाटी में दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की। भारतीय जांच एजेंसियों ने इसके सरगना को हमले का मास्टरमाइंड बताया, जो पाकिस्तान की धरती से आतंकी साजिशों को अंजाम देता है।

भारत ने इस हमले का जवाब बिजली की तेजी से दिया। 6-7 मई की रात 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तानी क्षेत्र में नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इन हमलों में सौ से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें मुजफ्फराबाद और मुरीदके जैसे इलाके शामिल थे, जहां 2008 के मुंबई हमले के गुनहगारों को प्रशिक्षण दिया गया था। यह कार्रवाई न केवल आतंकी नेटवर्क के लिए करारा झटका थी, बल्कि एक सख्त संदेश भी था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर कोई समझौता नहीं करेगा।

भारत की प्रतिक्रिया यहीं नहीं रुकी। मई 2025 में सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों में भेजे गए। इनमें अल्जीरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और यूएई जैसे देश शामिल थे। 51 सांसदों, राजनयिकों और पूर्व नौकरशाहों ने एकजुट होकर पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को बेनकाब किया। इन दौरों ने वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया और पाकिस्तानी दुष्प्रचार को ध्वस्त कर दिया। यह कूटनीतिक आक्रामकता इतनी प्रभावी थी कि अमेरिका ने इस संगठन को आतंकी सूची में शामिल करने का फैसला लिया, जो भारत की रणनीति की जबरदस्त जीत है।

अमेरिका का यह कदम केवल प्रतीकात्मक नहीं है। विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल होने से इस संगठन पर वित्तीय प्रतिबंध, यात्रा पाबंदियां और इसके नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और भारत के साथ सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बयान में पहलगाम हमले को 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक बताया गया, जिसने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। इस संगठन को लश्कर-ए-तैयबा के साथ जोड़ते हुए अमेरिका ने इसकी संलिप्तता को पूरी तरह उजागर कर दिया।

इस संगठन की स्थापना के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ माना जाता है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के दबाव का सामना करना पड़ा। इसे 'स्वदेशी' संगठन के रूप में पेश कर अपनी संलिप्तता छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत और अमेरिका ने इस नकाब को पूरी तरह उतार दिया। यह संगठन न केवल लश्कर के वित्तीय चैनलों का इस्तेमाल करता है, बल्कि ऑनलाइन भर्ती और आतंकी प्रचार में भी सक्रिय है।

पहलगाम की घटना और इसके बाद की कार्रवाइयों ने साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग अपरिहार्य है। भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत, साथ ही अमेरिका का यह कदम, आतंकवादियों और उनके समर्थकों के लिए सख्त चेतावनी है। भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' और वैश्विक मंचों पर अपनी बात रखकर यह साफ कर दिया कि वह न केवल अपने नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी हर कदम उठाएगा।

यह त्रासदी उन 26 परिवारों की कहानी है, जो कश्मीर की वादियों में सुकून की तलाश में गए थे, लेकिन आतंक की भेंट चढ़ गए। उनकी हत्या ने सवाल उठाया कि आखिर मानवता कब तक इस बर्बरता का शिकार बनेगी? लेकिन भारत और उसके सहयोगियों की एकजुटता ने यह उम्मीद जगाई है कि आतंकवाद के खिलाफ यह जंग निर्णायक मोड़ पर है। यह लड़ाई न केवल हथियारों से, बल्कि साहस, एकता और सच्चाई से जीती जाएगी।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

साध्वी बनने का नया ट्रेंड: त्याग की ओट में सुख का ब्रांड?

प्रियंका सौरभ

बचपन में हम सुनते थे कि साध्वी वह होती है जो मोह, माया, श्रृंगार, आकर्षण और सांसारिक जिम्मेदारियों से ऊपर उठ गई हो। वह जो खुद को समर्पित कर दे — ध्यान, साधना और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। आज की दुनिया में जब हम 'साध्वी' शब्द सुनते हैं, तो कल्पना में कोई ध्यानमग्न स्त्री नहीं आती, बल्कि किसी मंच पर तेज रोशनी में प्रवचन देती, डिज़ाइनर केसरिया वस्त्रों में सजी-धजी, सोशल मीडिया पर हजारों अनुयायियों वाली कोई 'आधुनिक साध्वी' उभर आती है।

अब साध्वी बनने का अर्थ आत्म-त्याग से नहीं, एक नई जीवन शैली से जुड़ गया है — जिसमें भोग त्यागने का दावा तो है, लेकिन सुख और लोकप्रियता का उपभोग भलीभांति जारी है। त्याग के नाम पर अब एक सुरक्षित ब्रांडिंग की जाती है, जिसमें स्त्री घर-परिवार, विवाह और सामाजिक दायित्वों से अलग होकर एक आध्यात्मिक आभामंडल रचती है — जिसमें चमक होती है, भीड़ होती है, डोनेशन होते हैं, देश-विदेश की यात्राएं होती हैं, पर आत्मसंयम और आत्मचिंतन का गहराई से कोई वास्ता नहीं होता।

यह प्रवृत्ति कोई आध्यात्मिक जागरण नहीं, बल्कि एक रणनीतिक पलायन है — जहाँ स्त्रियाँ संसार से भागती नहीं, बल्कि उसे अपने तरीके से नया आकार देती हैं, अपनी सुविधाओं और अपेक्षाओं के अनुसार। वे कहती हैं — हमने सब त्याग दिया, पर वास्तव में उन्होंने वही त्यागा जो उन्हें परेशान करता था — जिम्मेदारी, अपेक्षा, उत्तरदायित्व, और रिश्तों का बोझ। लेकिन उन्होंने अपना 'मैं' नहीं त्यागा, अपनी 'महत्ता' नहीं छोड़ी।

आज की कई तथाकथित साध्वियाँ सार्वजनिक मंचों पर उपदेश देती हैं कि भोग एक भ्रम है, गृहस्थी एक बंधन है, स्त्री का असली रूप वही है जो भीतर मौन हो और बाहर समर्पण में हो। लेकिन जब वही साध्वी इंस्टाग्राम पर फ़िल्टर लगाकर वीडियो अपलोड करती है, जब वह अपने हर कार्यक्रम का विज्ञापन करवाती है, जब उसके आयोजनों में विशेष पास और वीआईपी दीर्घा होती है — तब यह सवाल उठता है कि यह आध्यात्म है या महज एक सफल जनसंपर्क योजना?

पुराने समय में साध्वी बनना साहस का काम था। एक स्त्री जब दुनिया से अलग होती थी, तो उसे हर कदम पर समाज से टकराना पड़ता था। आज, जब कोई कहती है — मैं अब साध्वी हूँ — तो उसकी हर सामाजिक आलोचना चुप हो जाती है। क्योंकि हम यह मान बैठे हैं कि जो स्त्री केसरिया पहन ले, सिर पर घूंघट रख ले, और संस्कृतनिष्ठ भाषा में बोले — वह अब "देवी" है, उससे सवाल नहीं किए जा सकते।

इस प्रवृत्ति में सबसे बड़ा संकट यह है कि यह स्त्रियों को एक नया पलायन रास्ता दे रही है — आत्म-निर्माण के नाम पर आत्म-दंभ की गली। वे ना तो घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती हैं, ना कार्यक्षेत्र की स्पर्धा में उतरना चाहती हैं, ना परिवार, समाज या राजनीति से टकराना चाहती हैं। उन्हें चाहिए एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वे पूजी जाएं, पर जांची ना जाएं। साध्वी बनना उस 'पावन छवि' का माध्यम बन गया है, जो न किसी से प्रश्न करवाती है, न उत्तर देने को बाध्य करती है।

जब कोई साधारण महिला मानसिक थकावट से जूझती है, तो उसे "आराम करो", "खुद को समय दो" जैसा कहकर चुप करा दिया जाता है। पर जब कोई कहती है "मैं अब साध्वी बन गई हूँ", तो उसकी थकान को आध्यात्मिक महाकाव्य बना दिया जाता है। उसे मंच मिलता है, मीडिया का समर्थन मिलता है, और अनुयायियों की भीड़ बन जाती है।

यह साध्वी अब माइक पर बोलती है — "मैंने सब त्याग दिया", पर त्यागने के बाद जो मिला — वह कोई सामान्य गृहिणी कभी नहीं पा सकती। वह प्रवचन देती है, लेकिन कभी स्त्री अधिकार, सामाजिक न्याय, या आर्थिक समानता की बात नहीं करती, क्योंकि यह विषय उसके स्वनिर्मित आध्यात्मिक क्षेत्र को असुविधाजनक बना सकते हैं। वह किसी सरकार से नहीं टकराती, किसी असमानता पर नहीं बोलती, बस ध्यान, मन, आत्मा और जीवन का चक्र रचती रहती है।

इसे ही हम कह सकते हैं — "परिष्कृत भोग"। यह ऐसा भोग है जो सीधे भौतिक वस्तुओं में नहीं, पर ध्यान, सत्ता, मान्यता और प्रतिष्ठा के माध्यम से प्राप्त होता है। यह वासना नहीं, लेकिन 'विख्याति की भूख' जरूर है। इसमें श्रृंगार नहीं, परंतु आत्म-प्रदर्शन की आकांक्षा जरूर है। इसमें कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं, पर सामूहिक नियंत्रण की छाया ज़रूर है।

समाज, विशेषकर पुरुष प्रधान मानसिकता, को यह भूमिका बेहद स्वीकार्य लगती है। उसे वह स्त्री नहीं चाहिए जो सवाल करे, विचार करे, संघर्ष करे। उसे चाहिए 'आज्ञाकारी साध्वी', जो धर्म की ओट में चुप रहे और 'शांतिपूर्ण अध्यात्म' का चेहरा बने रहे। ऐसे में साध्वी बनना एक सुरक्षित मंच बन जाता है — जो न केवल स्त्री को उसके भीतर के प्रश्नों से बचाता है, बल्कि समाज की अपेक्षाओं को भी पूर्ण करता है।

इसलिए आज की कई साध्वियाँ असल में 'त्यागिनी' नहीं, बल्कि ऐसी महिलाएँ हैं जो जीवन से थकी हैं, रिश्तों से टूटी हैं, समाज से असंतुष्ट हैं, और इस असंतोष को 'ईश्वर की खोज' में छुपा देती हैं। वे चाहती हैं कि उन्हें अब कोई कुछ न कहे, कोई अपेक्षा न रखे, लेकिन सब उनका सम्मान करें, सब उन्हें सुनें, सब उन्हें मानें। यह आध्यात्म नहीं, 'सामाजिक चतुराई' है।

इस आधुनिक अध्यात्म में त्याग के स्थान पर मंच है, तपस्या के स्थान पर लाइमलाइट है, और शांति के स्थान पर डिजिटल ग्लैमर है। यह ऐसा अध्यात्म है जहाँ मोक्ष तो अभी भी लक्ष्य बना है, लेकिन रास्ता अब यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम लाइव और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से तय किया जाता है।

इसलिए हमें यह समझना होगा कि त्याग केवल कपड़ों से, बालों से या वाणी से सिद्ध नहीं होता। उसका संबंध मन से, आचरण से और नीयत से होता है। जब तक साध्वी बनने की प्रक्रिया आत्ममंथन की नहीं, बल्कि आत्म-प्रदर्शन की बनी रहेगी, तब तक यह साध्वी संस्कृति असली साधना को निगलती रहेगी।

यह कोई विरोध नहीं, एक विनम्र आग्रह है — स्त्रियाँ अगर साध्वी बनती हैं, तो उन्हें सचमुच साधना करनी चाहिए। मंचों से उतर कर उन विषयों पर बोलना चाहिए जिनसे समाज डरता है। उन्हें केवल ध्यान नहीं, चिंतन और आंदोलन का रास्ता भी अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर हर स्त्री साध्वी बन कर चुप हो जाएगी, तो वह परिवर्तन कौन लाएगा? त्याग वह नहीं जो दिखे, त्याग वह है जो भीतर से किया जाए। और भोग केवल इन्द्रियों से नहीं होता, वह प्रशंसा, अहंकार और पहचान के माध्यम से भी आता है।

जब तक हम इस नये 'साध्वी ट्रेंड' को नहीं समझेंगे, तब तक आध्यात्म भी एक उद्योग, एक शैली, एक मार्केटिंग मॉडल बना रहेगा — जिसमें भोग त्याग के कपड़े पहनकर हर मंच पर मुस्कराता रहेगा।

भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट (रजि.) का आठवाँ स्थापना दिवस समारोह 26 अगस्त को

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। रुक्मणि विहार, सैक्टर-1 स्थित भक्ति धाम में भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, पटियाला/वृन्दावन का आठवाँ स्थापना दिवस समारोह 26 अगस्त 2025 को प्रातः 09 बजे से अत्यंत हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा।

स्थापना दिवस समारोह के समन्वयक डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत कल्याणम् करोति के सचिव सुनील शर्मा के सहयोग से निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर लगाया जाएगा।जिसमें भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, पटियाला/वृन्दावन के द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, बैसाखी, वॉकर, व्हीलचेयर आदि सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।साथ ही संत, ब्रजवासी, वैष्णव सेवा एवं वृहद भंडारा आदि के कार्यक्रम सम्पन्न होंगे।

भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष के. एल. बंसल, उपाध्यक्ष नरेश गोयल, मुख्य सलाहकार डॉ. आर. के. गर्ग एवं महामंत्री संदीप कुमार सिंगला आदि ने सभी से इस समारोह में शामिल होने का आग्रह किया है।

पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विमानन एवं ड्रोन संस्थान का उद्घाटन किया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हॉल में (आईएडीआई) अंतर्राष्ट्रीय विमानन एवं ड्रोन संस्थान का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राजस्थान के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कलराज मिश्र और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी ने किया। इस दिल्ली अशोक विहार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय विमानन एवं ड्रोन संस्थान के उद्घाटन के मौके पर इस कार्यक्रम में अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, उद्योग जगत के दिग्गजों और विमानन क्षेत्र के उत्साही लोगों ने युवाओं को सशक्त बनाने और ड्रोन एवं विमानन प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने की एक ऐतिहासिक पहल का जश्न मनाया। इस अवसर पर संस्था के मुख्य संरक्षक डॉ. एच.सी. गणेशिया जो एक प्रसिद्ध अधिवक्ता ने भी एक एक विशेष संबोधन दिया। डॉ. गणेशिया ने विमानन और ड्रोन नवाचार में भारत के भविष्य को आकार देने में (आईएडीआई) जैसे संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में एएएफटी के संस्थापक डॉ.संदीप मारवाह, वरिष्ठ पायलट अनिल शर्मा (सेवानिवृत्त), राजस्थान के भरतपुर की प्रथम महिला पायलट कैप्टन गरिमा गणेशिया और सुश्री एस्टर नोरोन्हा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. राजेश कुमार, डॉ. पंकज सिंह, मनुज ठाकुर, श्रीमती परमजीत कौर (वरिष्ठ केबिन क्रू कतर एयरवेज़), सुश्री दीपिका धवन, सुश्री पूनम सेठी और राकेश छाबड़ा सहित एक समर्पित टीम द्वारा किया गया, जिन्होंने एक सुचारू और प्रभावशाली कार्यक्रम सुनिश्चित किया। कार्यक्रम का एक रोमांचक आकर्षण ए एंड एस क्रिएशंस के संस्थापक सुमित सभरवाल और उनकी समर्पित टीम द्वारा कई उन्नत ड्रोनों की प्रस्तुति थी।

एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन का तीन दिवसीय बिहार दौरा संपन्न, किशनगंज,अररिया, सुपौल में हुआ भव्य स्वागत

परिवहन विशेष न्यूज

पटना/किशनगंज/अररिया/सुपौल: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन और बिहार प्रदेश संयोजक सूर्यकांत कुमार सिंह का तीन दिवसीय बिहार दौरा हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरे के दौरान किशनगंज होटल दफ्तरी पैलेस में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में दोनों नेताओं का कार्यक्रम में जोरदार स्वागत किया गया। यह दौरा राकांपा के अल्पसंख्यक समुदाय के बीच संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

मधुबनी, सुपौल में जमीयतुल कासिम दारूल उलूम अल इस्लामिया में आयोजित सम्मान समारोह का नेतृत्व नाजिम मुफ्ती अंसार कासमी ने किया। इन समारोहों में शाहजहां शाद, कारी शमशेर सहित सैकड़ों मुफ्ती, मौलवी और दारूल उलूम के तालिब-ए-इल्म (छात्र) शामिल हुए। कार्यक्रम में राकांपा के अल्पसंख्यक विभाग की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेष रूप से समुदाय के उत्थान, शिक्षा, और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। उपस्थित लोगों ने नेताओं के सामाजिक कार्यों और उनके नेतृत्व की सराहना की।

राकांपा बिहार के मीडिया प्रमुख रंजन प्रियदर्शी ने बताया कि यह दौरा पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के बीच राकांपा की पहुंच को मजबूत करना और सामाजिक कार्यों को गति देना था। एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता को बढ़ावा देने, शिक्षा के प्रसार, और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, ₹राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन माननीय अजित पवार साहेब अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे नेता अजित पवार साहेब के महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किए गए विकास कार्यो के तर्ज पर बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में कई नई योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय का हर व्यक्ति सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके।₹

सैयद जलालुद्दीन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में एनसीपी राज्य में चुनाव में सभी पार्टी से अधिकतम सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार बनाने का इरादा रखती है

बिहार प्रदेश संयोजक सूर्यकांत कुमार सिंह ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि बिहार में राकांपा की गतिविधियों को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है। उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा, ₹हमें समाज के हर वर्ग तक पहुंचना है और उनके विकास के लिए मिलकर काम करना है। राकांपा का लक्ष्य बिहार में सामाजिक समरसता और प्रगति को बढ़ावा देना है।₹

सम्मान समारोह में स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा गया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने सैयद जलालुद्दीन और सूर्यकांत कुमार सिंह के नेतृत्व को प्रेरणादायक बताया और उनके प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में शामिल मुफ्ती और मौलवियों ने भी राकांपा के सामाजिक और शैक्षिक कार्यों की प्रशंसा की और इसे समुदाय के लिए एक सकारात्मक पहल बताया।

रंजन प्रियदर्शी ने आगे बताया कि इस दौरे से राकांपा की बिहार में स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा, ₹यह दौरा न केवल संगठन के लिए बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। राकांपा बिहार में सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।₹ इस दौरे के दौरान कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राकांपा के साथ जुड़ने की इच्छा जताई, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ और मजबूत होने की उम्मीद है।

यह दौरा न केवल राकांपा के लिए बल्कि बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर था, जहां सामाजिक एकता और विकास के नए रास्ते खोले गए। राकांपा के नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना और बिहार में समग्र विकास को बढ़ावा देना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एपस्टीन मामले पर अपने ही समर्थकों से घिरे-क्लाइंट लिस्ट में नाम शामिल होने का संदेह-

कॉरपोरेटर पार्षद से लेकर विधायक सीएम तक व संसद से लेकर पीएम राष्ट्रपति तक को चुनाव में किए गए वादों को पारदर्शिता से पूर्ण कर सशक्त नेतृत्व करना समय की मांग- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सभी लोकतांत्रिक देशों में जनता अपनी व राष्ट्र की उन्नति विकास सुव्यवस्था कानून व्यवस्था व पारदर्शिता से काम करने व चुनाव में किए गए वादों को निभानेकी उम्मीद कर काबिल प्रत्याशी को वोट देकर कॉरपोरेटर से पीएम तक की कुर्सी पर पहुंचाती है, तो फिर उसचुने हुए व्यक्तित्व का कर्तव्य फ़र्ज़ बन जाता है,कि उन उम्मीदों वादों को पूरी जवाबदारी के साथ पूर्ण कर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, परंतु मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत सहित विश्व में कम ही ऐसे नेता हैं जो पूरी तरह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले दो दिनों से अमेरिकाके राष्ट्रपति ट्रंप पर एपस्टीन मामले में पूरी रिपोर्ट व कागजात सार्वजनिक करने के चुनाव में किए गए वादे पर खरा नहीं उतरते व डिपार्मेंट आफ जस्टिस व एफबीआई द्वारा संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा कि यह केस औपचारिक रूप से बंद करने की घोषणा की जाती है, तो ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सहित उनके अनेक समर्थक नाराज हो गए, व आंदोलन शुरू है। एक ओर रूस और यूक्रेन को तुरंत रोकने का वादा अभी पूरा नहीं हुआ हो रहाहै,तो दूसरी ओर एपस्टीन मामले की रिपोर्ट जारी नहीं कर उन्हें बंद करने का फरमान सुना दिया गया है, ट्रंप इन दोनों मामलों में फेल होते नजर आ रहे हैं।चूँकि एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन की क्लाइंट लिस्ट में ट्रंप भी शामिल है इसलिए मामला बंद करवाया है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एपस्टीन मामले पर अपने ही समर्थकों से घिरे-क्लाइंट लिस्ट में नाम शामिल होने का संदेह- चुनावी वादा पूरा नहीं करने पर समर्थक भड़के।

साथियों बात अगर हम एपस्टीन मामले को समझने की करें तो, गौरतलब है कि जेफ्री एपस्टीन अमेरिका का एक कुख्यात यौन तस्कर और अरबपति फाइनेंसर था, जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे। एपस्टीन ने साल 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी।हालांकि उसकी मौतके बाद भी उससे जुड़ी कईकहानियां अभी चलती रहती हैं। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने न्याय विभाग और एफबीआई को एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने से रोक दिया है। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ है। दरअसल कई लोगों के आरोप है कि एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में राष्ट्रपति ट्रंप का भी नाम है। कभी ट्रंप के समर्थक रहे और अब आलोचक एलन मस्क ने भी ऐसे ही आरोप लगाए हैं। कई रिपब्लिकन सांसद भी न्याय विभाग पर दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग हो रही है।एप्स्टीन केस- नाबालिग लड़कियों के शोषण का आरोप (1) जेफ्री एप्स्टीन को पहली बार 2006 में फ्लोरिडा के पाम बीच से गिरफ्तार किया गया। एप्स्टीन को वेश्यावृत्ति और नाबालिगों को लालच देने के लिए दोषी ठहराया गया। (2) हालांकि,कुछ सौदेबाजी के बाद उसे सिर्फ 13 महीने की हिरासत मिली, जिसमें वर्क रिलीज की इजाजत थी (3) वर्जीनिया गिफ्रे नाम की महिला ने 2009 में आरोप लगाया कि एप्स्टीन ने उन्हें नाबालिग रहते यौन तस्करी के लिए मजबूर

किया। 2011 में गिफ्रे ने इस मामले में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का भी नाम लिया (4) 2015 में गिफ्रे ने एप्स्टीन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इसमें एप्स्टीन के प्रिंस एंड्रयू और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ रिश्तों का जिक्र था। (5) एप्स्टीन को 2019 में फिर से नाबालिगों की यौन तस्करी के मामले में गिरफ्तारकिया गया। गिफ्रे ने ही एप्स्टीन के खिलाफ अदालत में गवाही दी। (6) एप्स्टीन को वेश्यावृत्ति का नेटवर्क चलाने और बड़ी संख्या में महिलाओं के यौन शोषण और मानव तस्करी का दोषी ठहराया गया।एप्स्टीन की लिस्ट में बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन का नाम? (1) जनवरी 2024 में एक अमेरिकी कोर्ट ने जेफ्री एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए थे। इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसे हाई-प्रोफाइल लोगों के नाम थे। (2) इसमें बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रयू के साथ एप्स्टीन की पुरानी दोस्ती का भी जिक्र किया गया था। एप्स्टीन के मुताबिक क्लिंटन को कम उम्र की लड़कियां पसंद थीं। हालांकि, क्लिंटन के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो पाया।

साथियों बात अगर हम ट्रंप पर एपस्टीन मामले पर बढ़ते दबाव की करें तो, उन्होंने चुनावी सभाओं में वादा किया था कि वह इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देंगे, परंतु अभी एफबीआई व डीओज़े ने मामले को बंद करने की घोषणा करने पर बखेड़ा खड़ा हुआ है, मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके राजनीतिक विरोधी इस मुद्दे का इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि 'डेमोक्रेटिक पार्टी का नया घोटाला वही है, जिसे हम हमेशा जेफ्री एपस्टीन होक्स कहेंगे और मेरे पुराने समर्थक भी इस बकवास में पूरी तरह से फंस गए हैं। उन्होंने अपना सबक नहीं सीखा है और शायद कभी सीखेंगे भी नहीं।जेफ्री एपस्टीन मामले की फाइलों के खुलासे का दबाव ट्रंप प्रशासन पर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि ट्रंप इसे लेकर नाराज हो गए हैं और इस बार उन्होंने अपने समर्थकों को ही लताड़ लगा दी है। ट्रंप ने कहा कि उनके जो पूर्व समर्थक डेमोक्रेटिक पार्टी की बकवास में फंसकर एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, वे कमजोर हैं और अब उन्हें अपने इन कमजोर समर्थकों का साथ नहीं चाहिए। एपस्टीन मामले पर ट्रंप के इस बयान से साफ है कि रिपब्लिकन पार्टी में दरारें उभर रही हैं।कई लोगों के आरोप है कि एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में राष्ट्रपति ट्रंप का भी नाम है। कई रिपब्लिकन सांसद भी न्याय विभाग पर दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने शनिवार (12 जुलाई, 2025) को दावा किया कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो बाइडन और हिलेरी क्लिंटन ने मिलकर एपस्टीन फाइल्स तैयार की हैं? ताकि 2026 के मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके दरअसल अमेरिका में चर्चित जेफ्री एपस्टीन मामले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है,डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओज़े) और एफबीआई ने हाल ही में एक संयुक्त मेमो जारी कर इस केस की जांच को औपचारिक रूप से बंद करने की घोषणा की है, इस फैसले ने ना सिर्फ राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, बल्कि ट्रंप को भी हमलावर बना दिया है।

साथियों बात अगर हम इस मामले में एलन मस्क की भूमिका की करें तो,संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनियाँ के सबसे अमीर व्यक्ति के बीच दोस्ती में दरार पड़ गई है और यह एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने तक पहुँच गई है। राष्ट्रीय ऋण पर मतभेद से शुरू हुआ यह विवाद चरम पर पहुँच गया है, जब एलन मस्क ने ट्रम्प पर यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों को निजी संलिप्तता के कारण सार्वजनिक न करने का आरोप लगाया। बिना सबूत के पेश किया गया यह आरोप दोनों के बीच बढ़ती दरार को उजागर करता है और श्री ट्रम्प के इस हाई-प्रोफाइल यौन तस्कर से संबंधों की पुरानी खबरों की याद दिलाता है। इस साल एपस्टीन से जुड़ी कुछ फाइलें सार्वजनिक की गईं, जिनमें कई अहम जानकारी और उसके हाई-प्रोफाइल संपर्कों का जिक्र था,जेफरी एपस्टीन को ट्रंप का करीबी माना जाता था, इन फाइलों में ट्रंप का नाम नहीं मिला, लेकिन फिर भी ट्रंप और एपस्टीन के कथित संबंधों को लेकर लंबे समय से जांच होती रही है, मस्क ने 5 जून को सनसनीखेज दावा करते हुए कहा था कि ट्रम्प का नाम जेफरी एपस्टीन की फाइलों में शामिल है। मस्क ने एक्स पर लिखा था- अब बड़ा खुलासा करने का टाइम है।ट्रम्प का नाम एपस्टीन फाइलों में हैं। यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रम्प, आपका दिन शुभ हो।एक अन्य पोस्ट में कहा- इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोट कर लें। सच्चाई सामने आएगी। हालांकि, बाद में मस्क ने वो पोस्ट डिलीट कर दी थी और माना कि वह हद से ज्यादा बोल गए थे।मस्क ने एप्स्टीन के साथ ट्रम्प का एक वीडियो भी रिपोस्ट किया था।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एपस्टीन मामले पर अपने ही समर्थकों से घिरे- क्लाइंट लिस्ट में नाम शामिल होने का संदेह- चुनावी वादा पूरा नहीं करने पर समर्थक भड़के।एलन मस्क का आरोप एपस्टीन की क्लाइंट लिस्ट में ट्रंप भी शामिल इसीलिए एफबीआई डीओज़े ने मामला बंद किया।कॉरपोरेटर पार्षद से लेकर विधायक सीएम तक व संसद से लेकर पीएम राष्ट्रपति तक को चुनाव में किए गए वादों को पारदर्शिता से पूर्ण कर सशक्त नेतृत्व करना समय की मांग

इंतजार हुआ खत्म, एमजी ने दिल्ली में लॉन्च कर दिया एमजी चयन एक्सपीरियंस सेंटर

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में एमजी एक्सपीरियंस सेंटर भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल ब्रिटिश वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही दिल्ली में भी MG Select एक सपीरियंस सेंटर को शुरू कर दिया है। इसमें किस तरह की कारों को ऑफर किया जाएगा। आइए जानते हैं।

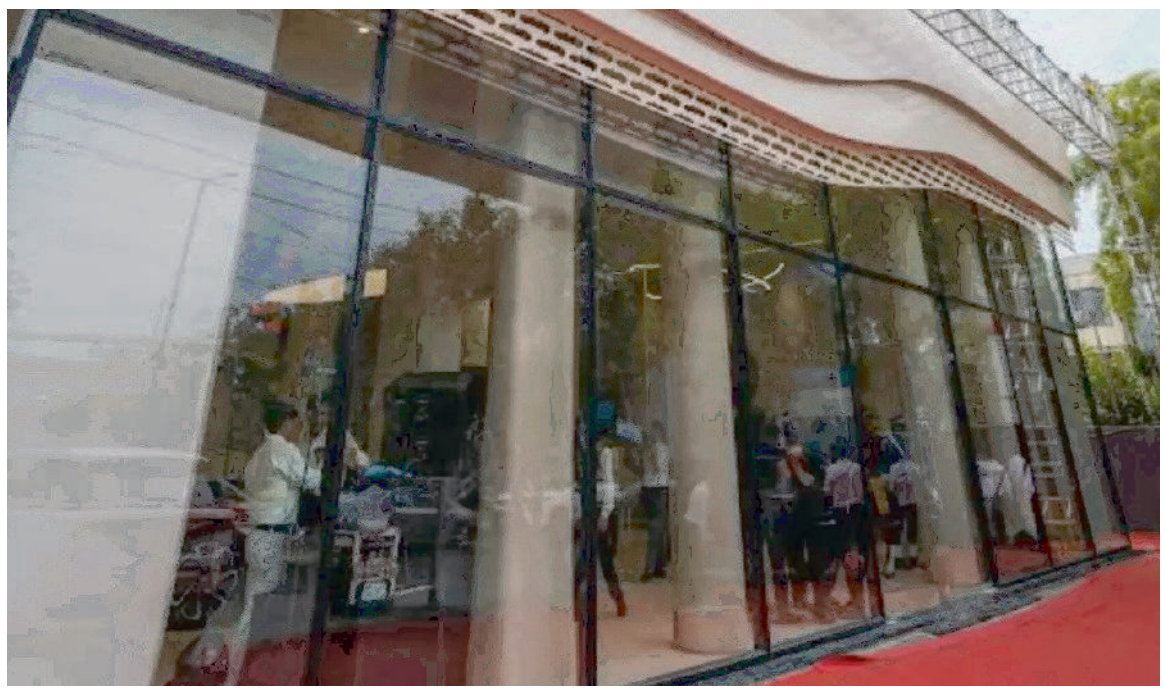

नई दिल्ली। ब्रिटिश वाहन निर्माता MG मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में ICE से लेकर EV सेगमेंट की कई कारों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से हाल में ही दिल्ली में MG Select एक्सपीरियंस सेंटर को शुरू किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

दिल्ली में शुरू हुआ MG Select एक्सपीरियंस सेंटर

एमजी मोटर्स की ओर से दिल्ली (MG Select Delhi) में अपने पहले एक्सपीरियंस सेंटर (MG Motors experience) को शुरू कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस एक्सपीरियंस सेंटर की शुरुआत दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की मौजूदगी में की गई।

प्रीमियम कारों को करेगी लॉन्च

निर्माता की ओर से इस तरह के एक्सपीरियंस सेंटर से प्रीमियम कारों को ऑफर किया जाएगा। फिलहाल इस सेंटर के जरिए निर्माता की ओर से MG M9 और MG Cyberster जैसी प्रीमियम कारों को ही ऑफर किया जाएगा।

जल्द लॉन्च होंगी कारें

एमजी सिलेक्ट एक्सपीरियंस सेंटर पर ऑफर की जाने वाली दोनों कारों को भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च किया जाएगा। MG M9 को 21 जुलाई 2025 को औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं MG Cyberster को भी भारत में 25 जुलाई 2025 के आस पास लॉन्च किया जाएगा।

13 शहरों में होगी उपलब्ध

कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि वह पहले चरण में देश के 13 शहरों में 14 MG Select के शोरूम शुरू करने जा रही है। इन शोरूम्स से ही प्रीमियम कारों को ऑफर किया जाएगा। जिन शहरों में इन कारों को सबसे पहले उपलब्ध करवाया जाएगा उनमें Delhi, Gurugram, Chandigarh, Mumbai, Thane, Pune, Surat, Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Kolkata, Kochi जैसे शहर शामिल हैं।

Auto Expo 2025 में हो चुकी हैं शोकेस

एमजी की ओर से जनवरी 2025 में Bharat Mobility 2025 के तहत आयोजित किए गए Auto Expo 2025 में Cyberster और M9 दोनों ही कारों को शोकेस किया जा चुका है।

काइनेटिक ग्रीनऔर टोनिनो लेम्बोर्गिनी ने भारत में लॉन्च की लग्जरी गोल्फ कार्ट, जानिए कितनी कीमत और फीचर्स

काइनेटिक ग्रीन और टोनिनो लेम्बोर्गिनी ने मिलकर लग्जरी गोल्फ कार्ट को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। यह गोल्फ कोर्स लग्जरी रिजाट्र्स और एयरपोर्ट्स के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। सिंगल चार्ज में इसे कितने किलोमीटर चलाया जा सकेगा। इसमें किस तरह के फीचर्स मिलेंगे। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में सामान्य उत्पादों के साथ ही लग्जरी उत्पादों की भी काफी ज्यादा मांग रहती है। इसी को देखते हुए Kinetic Green और Tonino Lamborghini की ओर से लग्जरी गोल्फ कार्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियतों को दिया गया है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च हुई लग जरी गोल फ कार्ट

भारत की Kinetic Green और इटली की Tonino Lamborghini की ओर से लग्जरी गोल्फ कार्ट को देश में लॉन्च किया गया है। यह उत्पाद दोनों कंपनियों की ओर से संयुक्त तौर पर बनाया गया है।

इटली में हुई डिजाइन

लग्जरी गोल्फ कार्ट को इटली में डिजाइन किया गया है और इसका उत्पादन भारत में किया गया है। इस कार्ट को गोल्फ कोर्स, लग्जरी रिजाट्र्स, एयरपोर्ट्स और औद्योगिक परिसर में उपयोग के लिए ऑफर किया गया है।

क्या है खासियत

लग्जरी गोल्फ कार्ट में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें दो, चार, छह और आठ सीटों का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा इसमें इंटेलीजेंट डैशबोर्ड, वायरलेस चार्जिंग, एलईडी लाइट्स, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, स्मार्ट स्टोरेज, फोल्डेबल विंडशील्ड, सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक की रेंज को दिया गया है। इसमें लगी मोटर से इसे 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। साथ ही 30 फीसदी ग्रेडिबिलिटी जेनरेट करने में सक्षम है। कार्ट को लेफ्ट हैंड ड्राइव के साथ ऑफर किया गया है, लेकिन इसे राइट हैंड ड्राइव के साथ भी खरीदा जा सकता है।

किन देशों पर होगा फोकस

लॉन्च के साथ ही इस बात की जानकारी भी दी गई है कि निर्माताओं का सबसे पहले किन देशों पर फोकस रहेगा। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले बहरीन, थाईलैंड, मालदीव और न्यूजीलैंड में लग्जरी गोल्फ कार्ट को ऑफर किया जाएगा। इसके बाद यूरोप के देशों में भी इसे बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

कितनी है कीमत

निर्माताओं की ओर से इसे दो वेरिएंट्स जेनेसिस और प्रेस्टीज में लॉन्च किया गया है। जिसमें से बेस वेरिएंट जेनेसिस की शुरुआती कीमत 10 हजार अमेरिकी डॉलर है और टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज की शुरुआती कीमत को 14 हजार अमेरिकी डॉलर रखा गया है।

टाटा, मारुति या हुंडई? जून 2025 में सब-4 मीटर एसयूवी की रेस में किसने मारी बाजी, टॉप-5 लिस्ट में कौन है शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

कॉम्पैक्ट एसयूवी की बिक्री भारतीय बाजार में हर महीने लाखों की संख्या में वाहनों की बिक्री की जाती है। कई निर्माताओं की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में कई विकल्प ऑफर किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2025 में किस एसयूवी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। Top-5 में किस निर्माता की किस एसयूवी को जगह मिली है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। हर महीने लाखों यूनिट्स की बिक्री की जाती है। जिनमें से सबसे ज्यादा योगदान एसयूवी सेगमेंट के वाहनों का होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में किस निर्माता की किस एसयूवी की सबसे ज्यादा मांग रही है। Top-5 में कौन सी एसयूवी को शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पहले नंबर पर रही Maruti Suzuki Brezza

मारुति सुजुकी की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में Maruti Suzuki Brezza को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी की बीते महीने के दौरान 14507 यूनिट्स की बिक्री हुई है। इसकी बिक्री में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10.14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

दूसरे नंबर पर रही Tata Nexon

टाटा मोटर्स की ओर से इस सेगमेंट में टाटा नेक्सन को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को ICE के साथ ही EV में भी ऑफर किया जाता है। बीते महीने के दौरान इसकी कुल बिक्री 11602 यूनिट्स की रही है। इसी के साथ Top-5 लिस्ट में इस एसयूवी को दूसरा स्थान मिला है।

तीसरे नंबर पर आई Tata Punch

टाटा मोटर्स की ओर से माइक्रो एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली टाटा पंच को भी काफी पसंद किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी की बीते महीने के दौरान 10446 यूनिट्स की बिक्री हुई है। इसके साथ ही इसे लिस्ट में तीसरे पायदान पर जगह मिली है।

अगले नंबर पर रही Maruti Suzuki Fronx

मारुति सुजुकी की ओर से सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में मारुति फ्रॉन्क्स की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी की बीते महीने के दौरान 9815 यूनिट्स की बिक्री की गई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी बिक्री में 1.31 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

Top-5 में शामिल हुई Mahindra XUV 3XO

महिंद्रा की ओर से भी इस सेगमेंट में Mahindra XUV 3XO को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी की बीते महीने के दौरान 7089 यूनिट्स की बिक्री की गई है।

नदी में महिंद्रा थार ले गए यूट्यूबर सौरव जोशी, वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया हो रही कार्रवाई की मांग

सौरव जोशी महिंद्रा थार का वायरल वीडियो यूट्यूबर सौरव जोशी ने हाल में ही अपने चैनल पर कुछ वीडियो अपलोड की हैं। जिसमें वह एक नदी में कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उनकी कार फंस जाती है तो उसे निकालने की कोशिश की जाती है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की मांग कर रहे हैं।

नई दिल्ली। प्रसिद्ध यू ट्यूबर सौरव जोशी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के मामले में फंस सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो के अपलोड होने के बाद कुछ लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किस तरह के वीडियो के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की मांग की जा रही है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

हो रही कार्रवाई की मांग

यू ट्यूबर सौरव जोशी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की मांग की जा रही है। सौरव जोशी ने कुछ समय पहले अपने चैनल पर दो वीडियो अपलोड किए हैं। जिसमें वह अपनी Mahindra Thar को जंगल और नदी में चला रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट

The Analyzer नाम के X अकाउंट पर सौरव जोशी का करीब दो मिनट का वीडियो पोस्ट किया गया है। जिसमें वह नदी के बीच फंसी हुई लाल रंग की महिंद्रा थार को पानी से निकालने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं।

वायरल हुई वीडियो

सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद कुछ ही समय में वह वायरल हो गई है। सिर्फ एक दिन में ही इस वीडियो को 1.57 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसके साथ ही पोस्ट पर लिखा है कि व्लॉगर सौरव जोशी अपने 20 मिनट के वीडियो कंटेंट के लिए नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। ' इन प्रभावशाली लोगों पर ऐसे कृत्यों के लिए भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य उत्तराखंड का प्रमुख आकर्षण है, अपनी घटिया सामग्री के लिए माफ़ करें।

लोग कर रहे कमेंट्स

वीडियो पर ज़्यादातर कमेंट्स में व्लॉगर के लापरवाह स्टंट और नदी को प्रदूषित करने के लिए उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। कई यूजर्स ने कमेंट्स में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को भी टैग किया है और व्लॉगर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

कुछ दिन पहले सीएम धामी के साथ थे सौरव जोशी

सौरव जोशी भले ही इस वीडियो में जीप को नदी के बीच पानी से निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही वह उत्तराखंड के सीएम के साथ पेड़ लगाते हुए नजर आए थे। सीएम धामी के साथ सौरव जोशी की फोटो के साथ एक यूजर शिवम ने ट्वीट भी किया है। साथ में लिखा है कि विडंबना यह है कि कुछ दिन पहले वह सीएम धामी के साथ पर्यावरण की रक्षा कर रहे थे।

टाटा पंच सीएनजी के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद कितनी जाएगी ईएमआई

कार वित्त योजना भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में Tata Punch CNG को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में सबसे सस्ती एसयूवी के तौर पर Tata Punch को ऑफर किया जाता है। Tata की इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata Punch CNG Price

टाटा मोटर्स की ओर से पंच एसयूवी को पेट्रोल के साथ ही सीएनजी इंजन के साथ भी ऑफर किया जाता है। CNG इंजन वाले बेस वेरिएंट के तौर पर Pure की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी के बेस वेरिएंट को 7.30 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 7.30 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 58 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स, करीब 35 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 8.23 लाख रुपये हो जाती है।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर Tata Punch के CNG इंजन वाले बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 6.23 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 6.23 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 10029 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car

अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 6.23 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 10029 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Tata Punch CNG के बेस वेरिएंट के लिए करीब 2.19 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 10.42 लाख रुपये हो जाएगी।

किनसे होता है मुकाबला

Tata की ओर से Punch को माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Nissan Magnite, Renault Kiger, Hyundai Exter जैसी एसयूवी के साथ होता है।

परीक्षा प्रणाली या 'सामाजिक भ्रमजाल ?

विजय गर्ग

शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला कहा गया है। यह व्यक्ति के ज्ञान, विवेक, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व विकास का माध्यम रही है। लेकिन आज की तारीख में यह उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया है। शिक्षा अब एक 'अंक- उद्योग' में तब्दील हो चुकी है, जहां ज्ञान की बजाय नंबर ही सफलता का पर्याय बन गए हैं। अब यह न तो चरित्र निर्माण का साधन रही, न ही सामाजिक चेतना का उपकरण। यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अंक दौड़ की एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में धकेलने वाला शोषण तंत्र बन गई है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में इस बार 45,516 छात्रों ने 95 फीसदी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, जो कुल परीक्षार्थियों का लगभग 1.92 प्रतिशत है। वहीं 1,99,944 छात्रों ने 90 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए, जो 8.43 प्रतिशत के करीब है। यह कोई अपवाद नहीं है हर साल यह आंकड़ा और ऊपर जा रहा है। लेकिन जब इन अंकों की असलियत जानने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले शिक्षकों की कार्यप्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो व्यवस्था मौन हो जाती है। यह एक साजिशन खड़ा किया गया भ्रमजाल है, जो शिक्षा को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बजाय एक कृत्रिम दौड़ में तब्दील कर रहा है।

शिक्षा के इस व्यवसायीकरण की गहराई को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस ढांचे को देखें जिसमें यह सब संचालित हो रहा है। 2019 में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कुल 22,030 स्कूलों में से लगभग 80 प्रतिशत स्कूल निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस आंकड़े में केवल 1,138 केंद्रीय विद्यालय, 2,727 सरकारी स्कूल, 598 नवोदय विद्यालय और 14 तिब्बती स्कूल शामिल हैं, जबकि शेष 17,553 निजी स्कूल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का एक

बड़ा हिस्सा निजीकरण के दबाव में है, जहां शिक्षा की गुणवत्ता नहीं, बल्कि परिणामों की संख्या मायने रखती है और जब यही 'अंकवीर' छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, जेईई या नीट में पहुंचते हैं, तो उनकी वास्तविक योग्यता सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में लगभग 11.35 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से मात्र 11,474 छात्र ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच सके। यही हाल साल 2024 का रहा। इस वर्ष लगभग 13.4 लाख छात्रों में से सिर्फ 14,627 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा तक पहुंचे। यानि बोर्ड परीक्षा के हाई स्कोरर प्रीलिम्स की पहली कसौटी पर ही फेल हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि बोर्ड परीक्षाओं में मिलने वाले ऊंचे अंक असल में बौद्धिक क्षमता या विषय की समझ का पैमाना नहीं हैं। यह मूल्यांकन प्रणाली रटंत विद्या तयशुदा उत्तरों और सजावटी भाषा पर आधारित है, जिसमें मौलिक सोच और विश्लेषण की कोई जगह नहीं।

यह समस्या केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिकता पूरे उत्तर भारत के शैक्षणिक वातावरण में व्याप्त है। स्कूलों में अब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि अच्छे परिणामों के जरिए स्कूल का नाम रौशन करना बन गया है। इसके उलट, दक्षिण भारत की तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर है। वहां के माता- पिता शिक्षा को केवल अंक पाने के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और कौशल निर्माण के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्र राष्ट्रीय परीक्षाओं में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वहां की शिक्षा प्रणाली में केवल परीक्षाफल नहीं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहारिकता और नवाचार को भी महत्व दिया जाता है। उत्तर भारत के अधिकतर स्कूलों में शिक्षण अब गाइडबुक, मॉडल पेपर और स्मार्ट आंसर पर आधारित हो गया है। शिक्षक भी केवल परिणाम उन्मुख होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके मूल्यांकन का आधार भी अब बच्चों के अंक बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नंबर की होड़ में बच्चों में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, हीन भावना और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। शिक्षा अब ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि एक दौड़ बन गई है, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाला ही विजेता माना जाता है।

सोशल मीडिया को निरंकुश नहीं आजादी

विजय गर्ग

कथित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंटी सोशल अभिव्यक्ति के चलते उपजी विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश की जरूरत बताते हुए देश की शीर्ष अदालत ने आत्म-नियमन की जरूरत बतायी है। दरअसल, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ, एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिस पर धर्म विशेष के देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के चलते कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत का कहना था कि नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का मूल्य समझना चाहिए। साथ ही इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आत्म-संयम बरतना चाहिए। कोर्ट ने चेताया है कि यदि सोशल मीडिया पर विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगता तो सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। जो एक अच्छी स्थिति नहीं होगी। निस्संदेह, समाज में विद्वेष व नफरत फैलाने वाले संदेश समरसता के भारतीय परिवेश के लिये गंभीर चुनौती बने हुए हैं। यही वजह है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि वह नियमन के लिये दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। दरअसल, अदालत का मानना था कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मिली आजादी असीमित कदापि नहीं है। यदि उससे सामाजिक समरसता में खलल पड़ता है तो सरकार को दखल देने का मौका मिलता है। जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिये अच्छा संकेत नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को सरकार नियंत्रित करे। सही मायनों में लोगों को समझना चाहिए कि देश की एकता व अखंडता बनाये रखना मौलिक कर्तव्य ही है। अदालत ने इस बाबत सवाल भी किया कि नागरिक स्वयं को संयमित क्यों नहीं कर सकते? कोर्ट का मानना था कि लोग तभी अभिव्यक्ति की आजादी का आनन्द ले सकते हैं जब यह संयमित ढंग से व्यक्त की जाए। शीर्ष अदालत की पीठ का मानना था कि नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए, तभी समाज में नफरत से मुकाबला किया जा सकता है। तभी हम गंगा-जमुनी संस्कृति के समाज का निर्माण कर सकते हैं।

वैसे कई राज्यों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के नियमन को लेकर सरकारी कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कई जगह विचारों की अभिव्यक्ति व कार्टून आदि बनाने को राजनीतिक दुराग्रह बताते हुए लोगों को गिरफ्तार तक किया गया है। जिसे सत्ताधीशों द्वारा बदले की भावना से की कार्रवाई बताया जाता रहा है। आरोप लगाया जाता रहा है कि सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के अनुरूप अमर्यादित अभिव्यक्ति पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन दूसरे राज्य में अन्य राजनीतिक दल की सरकार में यही अभिव्यक्ति अपराध बन जाती है। कहा जाता रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी द्वारा किसी मर्यादा को भंग करना घटिया या आपत्तिजनक तो हो सकता है लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। इसे कानून के आलोक में देखा जाना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों द्वारा सोशल मीडिया मंच का जमकर दुरुपयोग किया जाता रहा है। वहीं लोगों का कसूर यह है कि दल विशेष के एजेंडे वाली सामग्री को वे बिना पढ़े, दूसरे लोगों व समूहों में शेयर कर देते हैं। दरअसल,आम नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर उनका संयमित व्यवहार कैसा होना चाहिए। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही सामग्री की कितनी संवेदनशीलता है। कई लोग जाने-अनजाने में ऐसी सामग्री दूसरे व्यक्तियों व समूहों में शेयर कर देते हैं जो समाज विरोधी हो सकती है। दरअसल, वे उसकी मूल सामग्री को बनाने वाले के छिपे एजेंडे को नहीं भांप पाते। कभी-कभी भावावेश में लोग ऐसे कदम उठा देते हैं। निस्संदेह, कोई भी व्यक्ति भावनात्मक दुर्बलताओं से मुक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे शेयर की जा रही सामग्री की तार्किकता पर मंथन जरूर करना चाहिए। दरअसल, सोशल मीडिया आज एक ऐसा अस्त्र बन गया है जो जरा सी चूक से घातक साबित हो सकता है। वास्तव में हर नागरिक को इतना सचेत व जागरूक होना जरूरी है कि वह विभिन्न स्रोतों से आने वाली सामग्री से जुड़ी मंशा को समझ सके। निस्संदेह, संयमित, तार्किक व सतर्क प्रतिक्रिया से हम अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का आनन्द ले सकते हैं।

विज्ञान से छंटेगा अंधविश्वास का अंधियारा

विजय गर्ग

बिहार में पूर्णिया जिले के एक गांव टेटगामा में अंधविश्वास में अंधी भीड़ ने पांच निर्दोष जिंदगियों को निगल लिया। 'डायन' करार देकर एक ही परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह घटना केवल एक वीभत्स अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज में गहराई तक जड़ जमाए अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र और रूढ़िवादी मान्यताओं की डरावनी तस्वीर है, जो बताती है कि वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक चेतना के बीच अब भी एक बहुत बड़ी खाई मौजूद है।

आज जबकि विज्ञान ने हमें अति उन्नत प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष यात्रा, बायो इंजीनियरिंग और एआइ जैसे क्षेत्रों में पहुंचा दिया है, वहीं दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा तबका अभी भी नींबू- मिर्ची, पुनर्जन्म और भूत-प्रेत जैसी बातों में यकीन करता है। यह विसंगति केवल अशिक्षित वर्ग में ही नहीं है। इसकी जड़ें हमारी सामाजिक संरचना में छिपी हैं, जहां वैज्ञानिक नजरिए को पर्याप्त तवज्जो नहीं दिया जाता। आजादी के बाद वैज्ञानिक नजरिए को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थान और योजनाएं बनीं, किंतु वे समाज के सोच को बदलने में असफल रहीं। जिन तबकों को शिक्षा और समृद्धि नहीं मिली, वे चमत्कारों की आशा में अंधविश्वासों में चिपके रहे। और जिनमें समृद्धि आई, वे उसे खोने के डर से इन्हीं कुरीतियों का अनुसरण करते रहे।

दरअसल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन को तर्क, प्रमाण और विवेक के साथ समझने का तरीका है। यह नजरिया हमें सिखाता है कि किसी बात को तभी स्वीकारें जब उसके पक्ष में साक्ष्य हो। लेकिन हमारे समाज में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के बजाय उसका दमन किया जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक नजरिए का अभाव सामाजिक जीवन को दिशाहीन बनाए हुए है। संविधान ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नागरिक का मौलिक कर्तव्य घोषित किया है। इसके बावजूद भारतीय विज्ञान कांग्रेस जैसे मंचों पर छद्म-वैज्ञानिक दावों की प्रस्तुति, मीडिया में तर्कहीन विचारों का प्रचार व समाज में पाखंडियों की स्वीकृति यह दर्शाती है कि वैज्ञानिक दृष्टि हमारे समाज की मुख्यधारा नहीं बन सकी है।

इसलिए आज जरूरत है सामाजिक जागरूकता की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार की और यह समझने की कि जब हम विज्ञान को केवल तकनीकी लाभों तक सीमित रखते हैं और सोचने की स्वतंत्रता के रूप में नहीं अपनाते, तो हम विकास के नाम पर अंधेरे की ओर बढ़ते हैं। यह अंधेरा ही है, जिसने टेटगामा जैसे गांवों को आज भी 21वीं सदी के उजाले से दूर रखा है। हमें यह मानना ही होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही वह रोशनी है, जो अंधविश्वास के इस अंधेरे से समाज को बाहर निकाल सकती है। जब तक हम अपने सोचने के ढंग को नहीं बदलते, तब तक ऐसी घटनाएं हमारे विकास की सच्चाई को कठघरे में खड़ा करती रहेंगी।

मातृभाषा में शिक्षण से साक्षरता व शिक्षा की गुणवत्ता में आशातीत बदलाव लाया जा सकता है

विजय गर्ग

भले ही जनाधार खोते राजनेता नई शिक्षा नीति के तीन भाषा फॉर्मूले का विरोध अपनी राजनीति चमकाने के लिये कर रहे हों, लेकिन इस दिशा में किए गए नये प्रयोग आशा की नई किरण भी जगा रहे हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में जितनी आसानी और सहजता से सीख सकता है, उतना किसी थोपी गई भाषा में नहीं। तमाम शिक्षाविद् और भाषाविज्ञानी मानते रहे हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले शब्दों व परिवेशगत ज्ञान विद्यार्थियों को जल्दी सीखने में मददगार हो सकता है। देश में 121 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं मातृभाषाओं की संख्या सोलह से अधिक है। इतनी अधिक भाषायी विविधता वाले देश में, जब बच्चे अपने आसपास जो देखते और महसूस करते हैं, वो उनकी स्मृतियों में स्थायी बस जाते हैं। जब ये बातें उनके शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनती हैं, तो वे इसका आसानी से अंगीकार कर लेते हैं। कई शिक्षा आयोगों ने भी इसी बात की वकालत की है। इसी सोच के चलते देश के विभिन्न भागों में तीन भाषा फॉर्मूले को लेकर कई प्रयोग हो रहे हैं। इस रचनात्मक पहल के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। जिसके निष्कर्ष बताते हैं कि मातृभाषा में पढ़ाई करने से बच्चों की सीखने की गति तेज हुई है। इससे साक्षरता की दर में सकारात्मक बदलाव आया है। इतना ही नहीं इससे जहां छात्र-छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं उनकी कक्षा में सहभागिता भी बढ़ी है। सही मायनों में नई शिक्षा नीति में तीन भाषा फॉर्मूले का मकसद भी यही रहा है। विगत के अनुभव बताते हैं कि जब छात्र-छात्राओं को उनकी मातृभाषा से इतर अन्य भाषा में पढ़ाया जाता रहा है तो इसका असर उनकी सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। ऐसे में दूर-दराज के गांव-देहात या आदिवासी इलाकों से आने वाले विद्यार्थी अन्य शहरी बच्चों का मुकाबले करने में असफल हो जाते हैं। जिससे उनके स्कूल छोड़ने के प्रतिशत में भी वृद्धि होती है।

मौजूदा स्थितियों में तीन भाषा फॉर्मूले को लेकर किए जा रहे नये प्रयोग नई उम्मीद जगा रहे हैं। लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और ओडिशा के 13 जिलों में बच्चों को उनकी राज्यभाषा और अंग्रेजी के साथ-साथ मातृभाषा में पढ़ाने के लिये राज्य सरकारों के साथ मिलकर बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। इससे न केवल चयनित जिलों में बच्चों की साक्षरता दर में सुधार हुआ, बल्कि उनमें अन्य भाषा को सीखने की अभिरुचि भी बढ़ी है। एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में प्रारंभिक कक्षाओं में स्थानीय भाषा, सांस्कृतिक परंपराओं व परंपरागत ज्ञान को शामिल करने के लिये स्थानीय समुदायों की मदद भी ली गई। जिसमें स्थानीय परिवेश में उपजी लोककथाओं, स्थानीय संस्कृति आधारित कहानियां तथा कई पीढ़ियों से हासिल पारंपरिक ज्ञान को भी शामिल किया गया। बच्चों की पढ़ाई में रुचि बनी रहे, इसके लिये रचनाधर्मिता का सहारा भी लिया गया। जिसमें मौखिक शिक्षा प्रणाली का भी उपयोग किया गया। ऐसी शिक्षण सामग्री तैयार की गई जिससे बच्चे आसानी व रुचि के साथ आसानी से सीख सकें। मसलन कविता पोस्टर, कहानी के पात्रों के चित्र, वार्तालाप दर्शाने वाले चार्ट, शब्द कार्ड, वर्ण मात्रा कार्ड तथा चित्रों के जरिये कहानी बताने वाली किताबें इसमें शामिल की गईं। जिसने छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि जगायी और वे आसानी से सीखने लगे। उदाहरण के लिये छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जहां पचास फीसदी बच्चे हल्बी बोलते थे, वहां हिंदी में पढ़ाई करने से शिक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे थे। इस क्षेत्र में प्रारंभिक कक्षाओं में हल्बी को हिंदी के साथ जोड़कर पढ़ाया गया। इस शैक्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बाद सर्वे में यह सामने आया कि बस्तर में औसतन साक्षरता की दर में इकतीस फीसदी की, संख्या ज्ञान में पच्चीस फीसदी और वर्ण-अक्षर पहचान में छब्बीस फीसदी का सुधार हुआ। इसके अलावा मौखिक पाठन में चौदह फीसदी का सुधार आया। निश्चित रूप से इस अभिनव पहल ने देश को संदेश दिया कि मातृभाषा में शिक्षण से साक्षरता व शिक्षा की गुणवत्ता में आशातीत बदलाव लाया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर में इतिहास का विवाद

बेहतर होगा उमर अब्दुल्ला प्रदेश के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए समय निकालें, प्रदेश के विकास की कोई कारागार नीति बनाएं, शिक्षा की ओर ध्यान दें

श्रीनगर में शहीद स्मारक के नाम से एक स्थान है जहां हर साल 13 जुलाई को कुछ राजनीतिक व दूसरे लोग जाकर माथा निभाते हैं। इस स्थान पर 22 लोगों की कब्रें बनी हुई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 1931 में पुलिस की गोली से मारे गए थे। इस कब्रिस्थान को मजार-ए-शुहदा यानी शहीदों की मजार के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल श्रीनगर में अब्दुल कादिर खान नाम के एक अपराधी पर मुकद्दमा चल रहा था। यह अपराधी कौन था और इसे कौन लाया था, इसको लेकर अभी भी विवाद चलता रहता है। जाहिरा तौर पर तो यह कहा जाता है कि यह एक अंग्रेज अफसर का रसोइया था। यह रसोई का काम कितना करता था, इसके बारे में कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना निश्चित है कि यह शहर भर में मुस्लिम कश्मीरियों को हिंदू कश्मीरियों के खिलाफ भडक़ाने वाले भाषण करता था। ब्रिटिश सरकार जम्मू-कश्मीर के उस समय के महाराजा हरि सिंह के बहुत खिलाफ रहती थी क्योंकि महाराजा कभी उनके यूनियन जैक यानी झंडे को उतरवा देता था, कभी रेजीडेंट कमिश्नर की गतिविधियों को सीमित कर देता था। सबसे बड़ी बात यह कि महाराजा ब्रिटिश सरकार को गिलगित का इलाका पट्टे पर देने से इन्कार कर रहा था। इसलिए अब्दुल कादिर खान नाम का यह व्यक्ति सबसे ज्यादा गालियां महाराजा हरि सिंह को देता था। जाहिर है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इस अज्ञात कुल शील शख्स को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। खान की गिरफ्तारी के बाद वह अंग्रेज अफसर भी गायब हो गया।

यह भी चर्चा चलती रहती है कि नेशनल कान्फ्रेंस, जिसके मालिक उन दिनों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, के लोग भी उस अंग्रेज अफसर को जानते थे और वही उसे श्रीनगर लेकर आए थे। शेख अब्दुल्ला श्रीनगर और उसके आसपास लोकप्रिय तो हो रहे थे लेकिन सशक्त सैयद लॉबी उन्हें अपना प्रतिद्वन्द्वी मानती थी क्योंकि वह लॉबी मानती थी कि कश्मीरी मुसलमानों के वे स्वाभाविक नेता हैं। शेख अब्दुल्ला, जो कश्मीरी थे, अब व्यक्तिगत बातचीत में कहने लगे थे कि कश्मीरियों को अब बाहर से आए सैयदों के नेतृत्व की जरूरत नहीं है, बल्कि वे स्वयं अपने मसले सुलझाने में सक्षम हैं। यह सैयदों और कश्मीरी मूल के मुसलमानों का नेतृत्व को लेकर झगड़ा था। लेकिन सैयदों के पास एक तुरुप का पत्ता था जिसकी काट शेख अब्दुल्ला के पास भी नहीं थी। सैयद श्रीनगर की दो मुख्य मस्जिदों, खानगाहे मौला और जामिया मस्जिद पर काबिज थे। इन मस्जिदों में मजहबी कारणों से हर जुम्मे के दिन हजारों कश्मीरी आते थे। इस अवसर पर ये सैयद वायज कश्मीरियों को भावनात्मक स्तर पर मजहब से जोड़ कर अपने पाले में रखते थे। शेख अब्दुल्ला के पास इसकी काट नहीं थी। यह काट इस अज्ञात अंग्रेज अधिकारी ने अपने रसोइए के माध्यम से मुहैया करवाई थी। वह रसोइया अब जेल में बंद था और अंग्रेज अफसर अपना काम खत्म कर जा चुका था। अब अगला काम शेख अब्दुल्ला और उसके ग्रुप को करना था। इस काम के लिए अपने लोगों को जेल के बाहर एकत्रित किया गया और जेल के दरवाजे को तोड़ कर अब्दुल कादिर खान को मुक्त करवाने का आह्वान किया गया। पुलिस ने इस ग्रुप के लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह ग्रुप को न रुकने के लिए ही आया था। पुलिस ने गोली चला दी।

कुछ लोग मारे गए और बहुत से घायल हो गए। लेकिन मरने वालों में या घायल होने वालों में कोई शेख अब्दुल्ला के ग्रुप का था या नहीं, इसके बारे में अभी तक गहन चुप्पी का वातावरण है। कितने लोग मारे गए, इसके बारे में भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं हैं। अलबत्ता यह चर्चा गली बाजार में अभी तक चलती रहती है कि जानबूझ कर घायलों को अस्पताल ले जाने की बजाय मरने दिया गया ताकि मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए। शेख अब्दुल्ला ने यह बात फैलाना शुरू कर दी। एक घायल व्यक्ति ने उन्हें अपने पास बुला कर कहा कि हमने अपना काम कर दिया है, अब आगे का काम तुमने करना है। शेख अब्दुल्ला ने कभी यह नहीं बताया कि उस घायल की यह बात सुन कर, उन्होंने उसे अस्पताल ले जाने की भी कोशिश की या फिर उसकी मौत का इंतजार करते रहे, ताकि आगे का काम आसान हो जाए। घायल तड़पते रहे और कुछ लोग उनके मरने का इंतजार करते रहे, ताकि आगे का काम आसान हो जाए। कहा जाता है कि अंत में बाईस व्यक्ति दम तोड़ गए थे। कुछ गोली से और कुछ इलाज के इंतजार में। जो इलाज का इंतजार कर रहे थे, उनके आसपास के लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। जब यह इंतजार खत्म हुआ तो बाईस लोग यह दुनिया छोड़ कर जा चुके थे। जिनकी मौत मौके पर ही हो गई थी, उनके रिश्तेदार तो इसे 'रब्ब का भाना' मान कर सब्र भी कर लेते, लेकिन जिनकी मौत इंतजार में हुई थी, उनके रिश्तेदार बहुत साल तक उस राजनीति को कोसते रहे जिसने उनकी जान ली थी। जब रिश्तेदार अपने प्रियजनों की लाशें ले जाने लगे ताकि कब्रिस्तान में उनको सुपुर्दे खाक किया जा सके, तो शेख अब्दुल्ला के गुरप ने उन्हें ऐसा करने से रोका। राजनीति की भाषा में कहा जाए तो समझाया। इस समझाने का एक बहुत बड़ा कारण था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपनी अगली लड़ाई के लिए 'मजार-ए-शहीद' चाहिए थी। उसके लिए लाशें चाहिए थीं। वे लाशें अब जाकर किसी अज्ञात अंग्रेज अफसर और उसके रसोइए अब्दुल कादिर खान ने मुहैया करवाई थीं। ये लाशें किसी भी कब्रिस्तान में दफन हो जातीं तो उस अंग्रेज अधिकारी के श्रीनगर आने का उद्देश्य क्या रहता? श्रीनगर में रातोंरात चर्चा चलाई, ये लोग शहीद हुए हैं। कितने शहीद हुए, यह श्रीनगर में आज भी बहस का विषय बना रहता है।

लेकिन कब्रें 22 हैं तो माना जा सकता है 22 ही होंगे। पर लोगों की जुबान का क्या, जितने मुंह उतनी बातें। शहीदों की मजार होती हैं। इसलिए मजार-ए-शहीद अस्तित्व में आई। सैयदों के पास अपने केन्द्र थे और उनके मुकाबले में शेख अब्दुल्ला के पास भी एक भावनात्मक केन्द्र आ गया था। लेकिन यह मजार शेख को दे देने के बाद न कहीं उस अंग्रेज का पता चला और न ही अब्दुल कादिर खान का। शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 13 जुलाई की सार्वजनिक छुट्टी ही घोषित कर दी। बाकायदा मजार पर 13 जुलाई को हर साल मेला लगने लगा। बहुत से लोग विरोध भी करते कि उन बेगुनाह लोगों, जो राजनीति का शिकार होकर बेवजह मारे गए, पर अब तो राजनीति बंद करो ताकि वे कब्र के अंदर तो सुकून से पड़े रहें। लेकिन तब अनुच्छेद 370 लागू था। न कोई जम्मू वालों को पूछता था न लद्दाख वालों को। न कश्मीर के गुज्जरों की कोई हैसियत थी और न ही पहाडियों की। अब लोगों ने इस मजारे शहीद को राजनीति का अड्डा बनाने का विरोध किया तो सरकार ने 13 जुलाई की सार्वजनिक छुट्टी बंद कर दी। मजार पर जाकर लोगों के भावनात्मक शोषण को भी बंद किया। लेकिन कुछ लोगों की राजनीति का दाल-फुल्का इसी भावनात्मक शोषण के सहारे चलता है। इसलिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने बहुत हो-हल्ला किया। वे 13 जुलाई की बजाय 15 जुलाई को, जिस स्थान पर इन बाईस मृतकों की कब्रें बनी हुई हैं, उस स्थान की दीवार फांद कर अंदर घुस गए। कुछ समय वहां रह कर वापस आ गए। उनका कहना था कि वे वहां उनका फातिहा पढक़र आए हैं। बेहतर होगा उमर अब्दुल्ला प्रदेश के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए समय निकालें, प्रदेश के विकास की कोई कारागार नीति बनाएं, शिक्षा की ओर ध्यान दें, ग्रामीण इलाकों में सडक़ों की ओर ध्यान दें। गरीब और भोले-भाले कश्मीरियों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद कर यदि राज्य की असली समस्याओं की ओर ध्यान देंगे, तो ज्यादा लाभकारी होगा। कश्मीर के विकास के लिए केंद्र से जो बड़ी राशि आ रही है, उसका सदुपयोग तय करना होगा।

-कुलदीप चंद अग्निहोत्री

कुदरती आपदा में हमारी जिम्मेवारी व समाधान

पहाड़ों पर असंख्य गाडियों का बोझ, उनसे निकलने वाला धुआं और ऊष्मा क्या पहाड़ों के जलवायु को प्रभावित नहीं करते? हमारे पहाड़ देवस्थल थे, अतः इन्हें धूर्त, शराबियों का अड्डा और वेश्यालय न बनने दिया जाए। पहाड़ों की शांति-संस्कृति कायम रहनी चाहिए

जिला मंडी में आई आपदा ने पूरे प्रदेश को दर्द और पीड़ा में डुबो दिया है। बाढ़ पीड़ितों का दर्द देखा नहीं जा रहा। हर व्यक्ति अपने सामथ्र्य के अनुसार तन, मन और धन से उनका दर्द बांटने में लगा है। प्रकृति के कहर से अपनों को खोने के जख्म तो शायद ही कभी भर पाएंगे, परंतु जीवन को पटरी पर लाने के लिए भी कम मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही अनुकूल समय है जब मंदिरों, मठों के खजाने का मुंह आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए खोल दिया जाना चाहिए। आस्था के धन का मानवता के उद्धार के लिए प्रयोग हो, इससे बढिया मंदिरों के धन का सदुपयोग क्या हो सकता है?

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आपदा से लेकर अब तक निरंतर आपदा प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं। प्रशासन पूरी लगन से कार्य कर रहा है। पत्रकार बंधु अपनी जान जोखिम में डाल कर पल-पल की खबर सब तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही भयानक और दर्दनाक है। कहने में कोई संकोच नहीं कि अभी बरसात का मौसम बहुत लंबा चलेगा। पहाड़ सुरक्षित नहीं रहे, अब कौन जाने कब क्या हो? बारिश के मौसम में पूरे प्रदेश के बहुत से स्थानों पर घरों में दरारों का आना, जमीन का धंसना, पहाड़ों से मलबा गिरना जैसे समाचार अखबारों की सुर्खियां बन लोगों को चिंता में डाल कर बेचैन कर जाते हैं। परंतु प्रदेश की ऐसी स्थिति हुई क्यों, यह सोचना होगा। क्या पर्यावरण से छेड़छाड़ या शासकीय प्रशासकीय और राजनीतिक भ्रष्टाचार का नतीजा है यह सब? क्या मानव के लालच के आगे घुटने टेकती प्रकृति का प्रतिशोध माना जाए इसे या नदी-नालों का मार्ग अवरुद्ध कर घर बनाने का दुस्साहस कहें इसे? विकास को गति देती हमारी व्यवस्था में बैठे काले नागराजों की धृष्टता समझें इसे या अपरिपक्व एवं भ्रष्ट ठेकेदारों की अवैज्ञानिक ढंग से पहाड़ों के सीने पर चलाई गई पोकलेन का नतीजा समझें?

जिस प्रकार बाढ़ पीड़ितों का दुख बांटने के लिए हम एकजुट हुए, क्या उसी प्रकार पर्यावरण को बचाने के लिए हम एकजुट नहीं हो सकते? हम आपदा आने ही क्यों देते हैं? क्या हम आपदा को रोक नहीं सकते? सरकारों के अप्रिय फैसलों के खिलाफ हम अकेले-अकेले संघर्ष करने को बाध्य क्यों हैं? आज बिजली महादेव को रोपवे बनाने के खिलाफ वहां के लोग अकेले विरोध कर रहे हैं, हम सब प्रदेशवासी उनका साथ क्यों नहीं दे सकते? हम उनकी आवाज में अपनी आवाज क्यों मिला नहीं सकते? वो अपने देवस्थल को बचाना चाहते हैं, अस्था पर पर्यटन की छाया नहीं पडऩे देना चाहते, पेड़ों को कटने नहीं देना चाहते, पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों के स्वार्थ छुपे होते हैं, क्यों यह समझ नहीं पाते हम? पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर टूरिज्म विलेज का विरोध बस कुछ एक लोगों ने किया, क्यों सब साथ में नहीं चले? क्यों हम नहीं समझ पाते कि मौजूदा व्यवस्था में हमारी चुनी हुई सरकारों और हमारे चुने हुए गलत नुमाइंदों का अब सामाजिक कार्य की दृष्टि से आम जनता के उत्थान से कोई सरोकार नहीं रहा है। वो केवल अपने एवं अपने चेलों चांटों के घर भरने और सत्ता का मजा लूटने आते हैं। भू-माफिया, खनन माफिया, नशा माफिया, कोई बाहरी लोग नहीं होते, उनका सत्ता से गहरा नाता होता है, सत्ता आए या जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर सरकार में वो अपनी गोटियां फिट कर लेते हैं, यही कारण है कि आज तक अवैध खनन बंद नहीं हुआ क्योंकि हमारे नुमाइंदों को महंगे उपहार एवं नकदी इस माफिया से मिलती रहती है। लेकिन इस खनन का खामियाजा आम, गरीब और बेकसूर जनता को भुगतना पड़ता है। वर्ष 2023 की बरसात में जिला कांगड़ा के सुलाह एवं जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्रों में जमीन का धंसना और लोगों के घरों का जमींदोज होना आज तक कोई समझ नहीं पाया। यही वो क्षेत्र हैं जहां पिछले कई वर्षों से लगातार अवैध खनन हो रहा है जिसे रोक पाना किसी भी सरकार के वश में नहीं रहा अब तक, लेकिन क्यों? भ्रष्ट व्यवस्था से लडऩा आम आदमी के बस में नहीं, वो तो केवल अपनी बेबसी पर मात्र आंसू बहा सकता है।

जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया जूझ रही है, समय-समय पर संगोष्ठियां और चिंतन होते रहते हैं, परंतु कारगर कदम सरकारों द्वारा उठाए नहीं जाते, न ही आम आदमी जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत है। आय बढ़ाने के विभिन्न स्रोतों की तरफ ध्यान तो है, परंतु दुष्परिणामों की किसी को कोई चिंता नहीं। इसी कड़ी में सरकारें पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दे तो रही हैं, परंतु सोचना यह भी होगा कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग इस व्यवसाय से लाभान्वित हो रहे हैं और वो कौन लोग हैं? ऐसे लोग राजनीति के कितने करीब हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री से सरकार की कुल जीडीपी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? अब उन लोगों के विषय में भी सोचना होगा जिन्हें टूरिज्म इंडस्ट्री से पर्यावरण को हुए नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ा और अपना घर-बार, खेत-खलिहान, संपत्ति, सब गंवाना पड़ा।

स्वछता के मूल्यांकन में सुपर से ऊपर इन्दौर।

स्वतंत्र लेखक हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

जिसके संस्कारों में स्वच्छता बसी हुई हो वहां के 35 लाख नगारिकों के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024- 2025 में सुपर लीग में हम नम्बर वन बने ।वहीं हमारे मध्यप्रदेश के आठ शहरों में विभिन्न श्रेणियों में कई पुरस्कार प्राप्त किए। जिसमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास , शाहगंज, बुधनी शमिल हैं। इन्दौर जो लगातार स्वछता में सात बार अव्वल आ रहा था अब उस की सुपर लीग में भी जीत की नम्बर वन की पायदान से पुरे भारत में आठवीं बार फिर एक बार शहर इन्दौर ने परिस्थितियों से लोहा लेकर एक नई परिभाषा को मूल्यांकन कर ही दिया है , स्वच्छता अभियान की श्रेणी में नया इतिहास बना लिया है।आप को मालूम होगा जब इन्दौर ने शुरुआत की थी तों कचरों का पहाड़ समाने खड़ा हुआ था , चुनौतियां बड़ी थी और बहुत ज्यादा भी थी। एक और संसाधनों बहुत कमी हुआं करतीं थीं ।पर उन सभी से लड़कर चुनौतीयो से संघर्ष करते हुए जो स्थान प्राप्त हुआ, वहीं सच्चाई की कमाईं है । आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस नगर निगम इन्दौर के पास सब कुछ है विभिन्न सुविधाएं और कई प्रकार की कचरा को नष्ट करने के तरीकों से प्रतिदिन दिन रात काम चलता है।और अब इस अंकों की जादुई गणित की उच्चाइयों से आठवीं बार में हमारे शहर को जो अष्टसिद्धि की प्राप्ति हुई है वह सफ़ाई मित्रों की मेहनत से ही सम्भव हो सका है। जिनके लिए सुबह से लेकर देर रात तक लगातार ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने के योगदान से फिर एक बार सुपर लीग में नम्बर वन पर इन्दौर को आना बहुत ही गर्व की बात है । इस बात पर भी गर्व होना चाहिए की अब हमारे नगर निगम के अधिकारीयों व सफाई मित्रों व सुपरवाइजर आदि को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को स्वच्छ करने की अलग से जिम्मेदारी भी मिलीं है । और भी शहरों में हमारे यहां सभी जौहरी बन के भारत के सभी राज्यों में शहर शहर जाकर उन्हें भी साफ-सफाई के इस हवन-यज्ञ में कैसे आहुति दें इसकी शिक्षा देंगे। इन्दौर निरंतर हर साल लगातार सेंवन स्टारों के साथ अब सुपरलीग में भी अपना बेस्ट देकर बेस्ट मैनेजमेंट मार्डल बन चुका है। शहर इंदौर को स्वछता के अब तक आठ सितारे लग चुके हैं ।यहां पूरे भारत के लिए प्रेरणास्रोत बना हमारा इन्दौर की सबसे बड़ी ताकत कहें या सफलता का मूल मंत्र कहें वहां है यहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन , जों बहुत ही अच्छा व बेस्ट तरीका है , इसी के शत प्रतिशत प्रयास से घरों का कचरा निगम की कचरा गाड़ी में आता है और सीधे ट्रेचिंग ग्राउंड तक ले जाया जाता है ।इसी मजबूत कड़ी की बदौलत आज नगर निगम इन्दौर महानगर के सफ़ाई मित्र महिला पुरुष दोनों एक निडर व जांबाज सिपाहीयों के भांति ही दिन रात हर समय अपने शहर को चकाचक करनें में लगे रहते हैं। इसी का फल लगातार आठवीं बार स्वछता लीग में प्रथम पुरस्कार इन्दौर शहर को मिला है। जिस प्रकार पूरे भारत में 4 श्रेणियो में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। वह मूल्यांकन में 14 करोड़ लोगों ने पूरे भारत में भाग लिया। इसके लिए गह्वन निरीक्षण किया गया , भारत सरकार द्वारा इस मूल्यांकन में 11 लाख से ज्यादा घरों का मूल्यांकन भी इसमें शामिल हैं। तभी तो स्वच्छता के इस मूल्यांकन में सुपर से ऊपर जो शहर रहा वह इन्दौर है ।यहां आंकड़ों का नहीं इन्दौर नगर निगम की पूरी टीम मध्यप्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के मागदर्शन का फल है की सुपर लीग में इन्दौर नम्बर वन आया। यही दूरगामी

परिणाम है जो सबके समाने आयें है। ऐसे तो इन्दौर में चाहे होली हो दीपावली, ईद या गुरुनानक देव का प्रकाश पर्व या फिर महावीर जयंती व मोहर्रम का परम्परागत जुलूस इन सभी के पूरे होने के बाद जिस प्रकार शहर के उन जगहों पर जहां यह आयोजन होते हैं वहां त्वरित सफ़ाई मिशन शुरू कर के फिर से अपने इन्दौर को साफ व स्वच्छ कर देते हैं । जो यहां के सफाई मित्र हैं , हम इन्हें कर्मवीर योद्धा भी कहें सकते है। भारत में यह एक अजूबा ही हो रहा है पूरे भारत में साफ सफाई व स्वछता एक आंदोलन सा बन गया है। उस आंदोलन या मिशन का सिरमौर स्वच्छता का गुरु तो इन्दौर ही बना हुआ है ।जो सभी राज्यों व शहरों को सही व सटिक राह दिखा रहा। किसी शहर का लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन करना किसी महायज्ञ से कम नहीं है क्योंकि सफाई की इस अष्टसिद्धि की प्राप्ति के लिए शहर के नागरिकों समाजिक कार्यकर्ता समाजसेवी संगठन व अन्य धार्मिक संस्थाएं के सदस्य नेता राजनेता जनप्रतिनिधिगण संत महात्मा अधिकारी महापौर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सभी ने मिलकर इस स्वछता की तपोभूमि इन्दौर में महेनत की है और जो परिणाम आप सब के समाने दिख रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के हाथों से यही सफाई मित्र पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। शासन प्रशासन व नगर निगम वह जिम्मेदार नागरिकों ने अपने अपने स्तर पर अपना फ़र्ज़ निभाया हैं। यहां सबसे बड़ी बात है कि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की पहल से ही आज इन्दौर की स्वच्छ शहरों की यह यात्रा में कचरे से कंचन तक का यह सफर इन्दौर ने अपनी मेहनत से ही पूरा किया है ।यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी कचरों के बड़े बड़े पहाड़ों को हटाने वाला शहर इन्दौर अब भी घमंड लालच से दूर हैं। और वह सिर्फ जीत के लिए लक्ष्य की श्रम साधना का शंखनाद करने में लगा रहता है और हमेशा अव्वल ही आ रहा है। वह कोई दुसरा शहर नहीं सिर्फ वहां तो इन्दौर ही है । इन्दौर की नगर निगम की पूरी टीम साल भर लगातार बिना अवकाश के अपने अपने स्तर पर शहर को सफ़ाई के प्रति जागरूकता का पाठ पढ़ाती है व नागरिकों इसके फायदे भी समझती है ।स्कूल कालेजों में समाजसेवी संस्थाओं में स्वच्छता के लिए वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं जिससे यहां के नागरिकों में जनजागृति बनी रहे और साफ-सफाई के प्रति शहर में ना तो खुद कचरा फैलाये और ना किसी को फैलने दें । इन्दौर के लोग वह जिम्मेदार निगम कभी भी स्वच्छता के मामले में अति उत्साह में कमियों व नाकारात्मक पहलू से दूर नहीं भागते है । इसीलिए हर एक पहलू पर वैचारिक मंथन व चिंतन कर के आठवीं बार नम्बर वन के शिखर तक पहुंचने में इन्दौर सफल रहा है ।इस सभी कामों में सफ़ाई मित्र सबसे ज्यादा काम करते हैं इन कर्मवीर कर्मचारियों की सहारना पूरा शहर करता है यह उनके दिन रात के परिश्रम का फल ही है , जो दुसरे शहरों से आने वाले लोगों को भी दिखाई देती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के भारत में सफ़ाई स्वछता की जो बातें कही गई थी और जो लोग सुनते भी है की स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है तो उसी बात को जब लालकिले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से स्वछता की साधना की बात रखी थी तभी से साफ सफाई के महात्व को हमारा पूरा भारत मान भी रहा है और इस साफ सफाई के महत्व को समझ भी रहा है। तभी तो आठ सालों से मध्यप्रदेश के बहुत से शहर इस हवन-यज्ञ में अपनी अपनी आहुति देते आ रहे हैं। खासकर इन्दौर तो इस का सिरमौर के साथ स्वच्छता का गुरु भी बन गया है। हमारे इन्दौर को मालूम है की कोई भी तपस्या सिध्दी आसानी से नहीं मिलती इसके लिए कठिन साधना करना पढ़ती है । क्योंकि संघर्षों की भट्टी में तप तप कर ही सोना बनता है।जमीनी हकीकत से रूबरू होकर हर एक सफ़ाई मित्र कर्मवीर सारथी जो शहर के हितों में सफाई की इस महापूजा या यज्ञ में साधना कर रहे थे ।ऐसे सभी साधकों को दिल से नमन। इसी के बल पर एक बार इन्दौर फिर सिरमौर बन अव्वल हो गया है और एक नई भूमिका जो उसे मार्गदर्शन करने की मिलीं है उसमें भी वह टीम भावना व सभी के सहयोग से मिलकर भारत को दिशा दिखायेगा और अपनी कार्यसिद्धि के इस अटूट प्रयासों से इन्दौर की हर एक गली मोहल्ले हर एक क्षेत्र में हम सभी सफ़ाई मित्रों के साथ अपने शहर के नागरिक होने की जिम्मेदारी हम सभी निभायेंगे , और घर आफिस दफ्तर दुकानों से निकले वाले कचरे को अलग-अलग रख कर गीला सुखा अलग कर के ही कचरा गाड़ी वालों को देंगे ।हम शहरवासी रोको टोको को भी जारी रखेंगे, क्योंकि यदि कोई कचरा फैला रहा हो गंदगी कर रहा हो तो उसे सही गलत बतानें हेतु हम आगे आयेंगे । इन्हीं संयुक्त प्रयासों व सहयोग से इन्दौर को हमेशा आगे सफलता दिलाने में हम सभी मददगार साबित होते रहेंगे, यही संकल्प है हम सभी इन्दौर वासियों का जिससे हमारी युवा पीढ़ी को और बच्चों को साफ सफाई के बारे में जागरूक रहेंगे की भी प्रेरणा मिलती रहे। ऐसा करना हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि गंदगी से बिमारियों का सम्राज्य पनपता है। भविष्य में सफाई से ही स्वछता का सिरमौर बनाने में भारत के हर एक शहर राज्य आगे बढ़ेंगे , इसलिए हम सफ़ाई की अच्छी शुरुआत को प्रेरणा मानकर जब इन्दौर स्वच्छता में प्रथम आने के लिए आठवीं बार फिर जीत गया है तो आगे और उपलब्धि भी मिलना शेष है ।हमारा इन्दौर तो यही चाहता है कि अन्य राज्यों व शहरों को भी आगे आने का अटूट संकल्प लेना ही होगा। सिर्फ नगर परिषद , नगर निगम के भरोसे या गंदगी फैली हो या सफाई में लापरवाही जनता की हो या निगम की उसे छुपाना नहीं चहिए । सकारात्मक प्रयासों से एकजुटता से आपस में मिलकर हम यह वचन ले की हम शहर की जागरूकता के लिए सफ़ाई मिशन के लिए अपना नागरिक होने का सच्चा फ़र्ज़ निभायगे । क्यों की बिना मेहनत के साधना कैसे सफल होगी , इसलिए हमारे इन्दौर को अष्टसिद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत बहुत बधाई । आगे परिश्रम करना बहुत ज्यादा होगा , इन्दौर की दिवारो पर सनातन संस्कृति देशभक्ति के रंग के साथ साथ प्रकृति के करीब लाने हेतु 3 डी कलर में पूरे शहर की दीवारों पर तस्वीरें सभी को लुभाती है। और जो चीजें काम नहीं आती है और वह कचरें में अटाले में पड़ी थी उसी बेस्ट चीजों से कबडे से सफ़ाई दीदी और बब्बर शेर घोड़ा आदि बहुत सी कलाकृतियां बनाईं गई , जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। छोटी छोटी गलियों से कचरा उठाने के लिए इलेक्ट्रीक रिक्शा , छोटी गाड़ी भी घर घर जा रही है। तभी तो इन्दौर को स्वछता की प्रतिस्पर्धा अब किसी से नहीं है वह सुपर से ऊपर की इस जीत के लिए हमेशा से और भी कठिन साधना के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहेगा

लोकजीवन के अनगढ़ वैज्ञानिक और कलाकार

कुछ लोग किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि ज़िंदगी की हर सांस में अपनी कहानी लिखते हैं। उनके पास न डिग्रियों की शान होती है, न विश्वविद्यालयों की चमक, फिर भी वे समाज को वह अनमोल खजाना देते हैं जो सबसे अनमोल है—दिशा, गहराई और प्रेरणा। ये अनपढ़ ज्ञानी हैं, जिनका ज्ञान खेतों की माटी, जीवन की आग और पीढ़ियों की सीख से रचा होता है। उनका ज्ञान चुपके से बोलता है, मगर उसकी गूंज सदियों तक गूंजती है। ये वो नायक हैं, जो अपने समुदायों को नई राह दिखाते हैं और मानवता को उसकी जड़ों से जोड़े रखते हैं। चाहे वह गांव का हकीम हो, जो जड़ी-बूटियों से जीवन रंगता है, या बंजारा कलाकार, जो अपनी कला से सत्य को उकेरता है, या वह देहाती आविष्कारक, जो खेतों में क्रांति लाकर दुनिया को नई सोच देता है—ये सभी बिना किसी औपचारिक डिग्री के समाज के सितारे हैं।

गांव के किसी सुदूर कोने में, एक सादी-सी झोंपड़ी में बैठा वैद्य, जिसके चेहरे की झुर्रियों में अनुभव की गहरी किताबें और आंखों में नाड़ी की गति पढ़ने की प्राचीन कला बसी हो, वह भले ही किसी मेडिकल कॉलेज की डिग्री से अनजान हो, पर उसका ज्ञान किसी विद्वान से कम नहीं। वह न तो लैब में शोध करता है, न ही स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन टटोलता है, मगर जब वह तुलसी, नीम, गिलोय और अश्वगंधा का काढ़ा तैयार करता है, तो वह सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करता—वह रोगी के मन को आशा और सुकून का आलम देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (२०१०) के अनुसार, भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी 70-80% लोग आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर हैं। ये वैद्य, जिन्हें औपचारिक डिग्रियां नहीं सजातीं, अपने अनुभव और पीढ़ियों से चली आ रही ज्ञान की धरोहर के बल पर असंख्य परिवारों का सहारा बनते हैं। वे रोगी को महज एक मरीज नहीं मानते—वे उसके दुख, उसकी कहानी और उसकी जरूरतों को दिल से समझते हैं। उनका यह ज्ञान केवल जड़ी-बूटियों का मिश्रण नहीं, बल्कि विश्वास, संवेदना और मानवता का अनमोल संगम है—एक ऐसी विरासत, जो आधुनिक चिकित्सा की चकाचौंध में भी बेमिसाल और दुर्लभ है।

खानाबदोश कलाकार, समाज के वो अनमोल रत्न हैं, जो अपनी कला के जादू से ज़िंदगी की गहरी सच्चाइयों को उजागर करते हैं। बिना किसी रंगमंच की शोभा, बिना अभिनय की औपचारिक डिग्री, ये लोकगीत, कठपुतली, नुक्कड़ नाटक या नृत्य के ज़रिए दर्शकों के दिलों को न केवल छूते हैं, बल्कि उन्हें झकझोर कर सोचने पर मजबूर करते हैं। भारत में तमाशा, नौटंकी, भवई और रम्मत जैसी लोक कलाएँ आज भी ग्रामीण और शहरी दिलों को एक सूत्र में पिरोती हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट (२०19) बताती है कि भारत की 300 से अधिक लोक कला परंपराएँ आज भी जीवित हैं, और इनका संरक्षण इन्हीं अनपढ़ कलाकारों की बदौलत है। ये कलाकार अपने गीतों, कहानियों और प्रदर्शनों के ज़रिए जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और पर्यावरणीय संकट जैसी सामाजिक बुराइयों पर करारा प्रहार करते हैं। वे समाज का आलोचनात्मक आईना बनकर उसकी कमियों को उजागर करते हैं, और अपनी हल्की-फुल्की मुस्कान के साथ बदलाव की प्रेरणा जगाते हैं। उनकी कला महज मनोरंजन नहीं, बल्कि एक जीवंत सामाजिक आंदोलन है, जो बिना किसी डिग्री के समाज को नई सोच, नई राह और नई उम्मीद देता है।

ग्रामीण वैज्ञानिक, वो अनघट रचनाकार हैं जो खेतों की मिट्टी और खलिहानों की हवा में विज्ञान को साकार करते हैं। भारत, जहाँ 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, वहाँ ऐसे अनगढ़ नायक उभरते हैं, जो बिना किसी औपचारिक शिक्षा के नवाचार की मशाल जलाते हैं। मिसाल के तौर पर, गुजरात के मनसुखभाई प्रजापति ने मिट्टी से बना 'मिट्टीकूल' रेफ्रिजरेटर गढ़ा, जो बिना बिजली के भोजन को ठंडा रखता है। इस साधारण-सी खोज ने न केवल ग्रामीण भारत में क्रांति ला दी, बल्कि वैश्विक मंच पर भी प्रशंसा बटोरी। इसी तरह, तमिलनाडु के सुभाष पालेकर ने 'शून्य लागत खेती' का क्रांतिकारी मॉडल रचा, जिसे आज लाखों किसान अपनी आजीविका का आधार बना चुके हैं। ये ग्रामीण वैज्ञानिक, बिना किसी डिग्री के, अपनी गहरी पर्यावरणीय समझ और अनुभव की ताकत से ऐसी तकनीकें रचते हैं, जो स्थानीय चुनौतियों का समाधान तो करती ही हैं, साथ ही विश्व पटल पर भी प्रेरणा बनती हैं। उनकी हर खोज एक जीवंत गाथा है, जो सिद्ध करती है कि सच्चा विज्ञान डिग्रियों से नहीं, बल्कि धरती से जुड़े दिल और दिमाग से उपजता है।

ये अनपढ़ ज्ञानी समाज के सच्चे संरक्षक हैं, जो अपनी संस्कृति और नैतिकता की गहरी जड़ों को थामे, समाज को उसका असली चेहरा दिखाते हैं। जब दुनिया आधुनिकता की बेकाबू रफ्तार में अपनी पहचान खो रही है, तब ये लोग परंपराओं, मूल्यों और संस्कृति की मशाल जलाए रखते हैं। एक बुजुर्ग दादी, जो अपनी कहानियों के जादू से बच्चों के मन में नैतिकता और मानवता के बीज बोती है, या एक कुम्हार, जो चाक पर मिट्टी को गढ़ते हुए जीवन का गहन दर्शन सिखाता है—ये समाज के अनघट गुरु हैं। भारत में, मौखिक परंपराएँ और लोककथाएँ आज भी 70% से अधिक ग्रामीण आबादी के लिए शिक्षा का जीवंत स्रोत हैं। ये लोग न केवल ज्ञान की गंगा बहाते हैं, बल्कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर उसे मजबूत बनाते हैं। उनकी हर कहानी, हर कला, और हर सीख एक ऐसी धरोहर है, जो न सिर्फ अतीत को जीवित रखती है, बल्कि भविष्य को भी नई रोशनी देती है।

ये अनपढ़ ज्ञानी हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान डिग्रियों की चमक में नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई, संवेदना की सच्चाई और जिम्मेदारी की ताकत में बसता है। उनकी ज़िंदगी एक ऐसी जीवंत पाठशाला है, जिसका न कोई सिलेबस है, न कोई दीवार, फिर भी हर पल वह जीवन का नया सबक देती है। जब हम इन्हें "अनपढ़" कहते हैं, तो हम अपनी औपचारिक शिक्षा की तंग सीमाओं को ही उजागर करते हैं। क्योंकि जो बिना किताबों के जीवन का गूढ़ रहस्य समझ ले, जो बिना विश्वविद्यालय की डिग्री के समाज को नई राह दिखा दे, उसे अनपढ़ कहना ज्ञान की सबसे बड़ी अवमानना है। ये लोग न केवल समाज के प्रेरक हैं, बल्कि उस सच्चाई के प्रतीक हैं जो हमें बताती है कि ज्ञान का असली मंदिर मन, अनुभव और मानवता में बसता है।

आज के डिजिटल युग में, जब जीवन तकनीक की चकाचौंध में डूबता जा रहा है, इन अनपढ़ ज्ञानियों की प्रासंगिकता और भी चमक उठती है। वे हमें जताते हैं कि ज्ञान का असली मोल नौकरियों की दौड़ या डिग्रियों के ढेर में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान बनने और समाज की नि:स्वार्थ सेवा में है। ये लोग हमें प्रेरित करते हैं कि हम उनकी कहानियों को सुनें, उनके अनुभवों से सीखें और उनके योगदान को सम्मान दें। बिना किसी तामझाम के, चुपके से, मगर गहरे प्रभाव के साथ, ये समाज को नया आकार दे रहे हैं। उनका ज्ञान न तो डिग्रियों की बेड़ियों में जकड़ा है, न ही किताबों की स्याही में सिमटा है—वह उनकी मेहनत की माटी, उनकी संवेदना की गहराई और उनके जीवन की हर सांस में बिखरा है। बस हमें चाहिए एक नजर जो उसे देखे, एक दिल जो उसे समझे और एक मन जो उसका आदर करे।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

गाँव का अस्तित्व और पलायन

विवेक रंजन श्रीवास्तव

दुनिया में हमारे गांवो की विशिष्ट पहचान यहां की आत्मीयता,सचाई और प्रेम है .

विकास का अर्थ आर्थिक उन्नति से ही लगाया जाता है . हमारे गाँवो का ऐसा विकास होना चाहिये कि आर्थिक उन्नति तो हो किन्तु हमारे ग्रामवासियों के ये जो नैतिक और चारित्रिक गुण हैं , वे बने रहें . गांवो के आर्थिक विकास के लिये कृषि तथा मानवीय श्रम दो प्रमुख साधन प्रचुरता में हैं . इन्हीं दोनो से उत्पादन में वृद्धि व विकास संभव है . उत्पादकता बढ़ाने के लिये बौद्धिक आधार आवश्यक है जो अच्छी शिक्षा से ही संभव है .

आज वांछित सुविधाओं के अभाव में गांव व्यापक रूप से पलायन का दर्द झेल रहे हैं। किसान बड़े बड़े खेत बेचकर शहर में फ्लैट में रह रहे हैं. नई पीढ़ी खुद के खेत में मेहनत कर अनिश्चित आमदनी की अपेक्षा , शहर में किसी की नौकरी करके बंधी हुई तनख्वाह में गुजारा करना चाह रही है। छठ पूजा , ग्रीष्म अवकाश , दीपावली या अन्य त्यौहारों पर महानगरों से गांवों की ओर भागती भीड़ बताती है कि अभी भी लोगों की जड़े गांवों में ही हैं और यदि गांवों का समुचित विकास नीतिगत रूप से किया जाए तो वर्तमान पलायन रुक सकता है।

पुस्तकीय ज्ञान व तकनीक , शिक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं . ग्राम विकास के लिये तकनीकी शिक्षा के साथ साथ चरित्रवान व्यक्ति बनाने वाली शिक्षा दी जानी चाहिये . वर्तमान स्वरूप में शिक्षित व्यक्ति में शारीरिक श्रम से बचने की प्रवृत्ति भी स्वतः विकसित हो जाती है . यही कारण है कि किंचित भी शिक्षित युवा शहरो की ओर पलायन कर रहा है . आज ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो सुशिक्षित बनाये पर व्यक्ति शारीरिक श्रम करने से न हिचके.

स्थानीय परिस्थितियो के अनुरूप प्रत्येक ग्राम के विकास की अवधारणा भिन्न ही होगी जिसे ग्राम सभा की मान्यता के द्वारा हर ग्रामवासी का उसका अपना कार्यक्रम बनाना होगा .

गांव के विकास के लिए जहाँ भूमि उपजाऊ है वहां खेती, फलों फूलो बागवानी नर्सरी को बढ़ावा , व कृषि से जुड़े पशुपालन का विकास किया जाना चाहिए।

वन्य क्षेत्रो में वनो से प्राप्त उत्पादो से संबंधित योजनायें व कुटीर उद्योगो को और

बढ़ावा दिया जाना जरूरी है।

शहरो से लगे हुये गांवो में शासकीय कार्यालयो में से कुछ गांव में प्रारंभ किये जाने चाहिए जिससे शहर गांवों की ओर जाए तथा शहरो व गांवो का सामंजस्य बढ़े ।

पर्यटन क्षेत्रो से लगे गाँवो में पर्यटको के लिये ग्रामीण आतिथ्य की सुविधा सुलभ करवाना चाहिए ।

विशेष अवधारणा के साथ समूचे गांव को एक रूपता देकर विशिष्ट बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए जिससे ग्रामीणों में गर्व की अनुभूति हो और पलायन रुके । उदाहरण स्वरूप जैसे जयपुर पिंक सिटी के रूप में मशहूर है , किसी गांव के सारे घर एक से बनाये जा सकते हैं , उन्हें एक रंग दिया जा सकता है और उसकी विशेष पहचान बनाई जा सकती है , वहां की सांस्कृतिक छटा के प्रति , ग्रामीण व्यंजनो के प्रति प्रचार के द्वारा लोगो का ध्यान खींचा जा सकता है . वहां के वैशिष्ट्य को रेखांकित किया जाना चाहिए।

कार्पोरेट ग्रुपों द्वारा गांवों में अपने कार्यालय खोलने पर उन्हें करों में छूट देकर कुछ गांवो की विकास योजनायें बनाई जा सकती हैं ।

इत्यादि अनेक प्रयोग संभव हैं,पर हर स्थिति में ग्राम संस्कृति का अपनापन , प्रेम व भाईचारे को अक्षुण्य बनाये रखते हुये , गांव से पलायन रोकते हुये गाँवो में सड़क ,बिजली ,संचार ,

स्वच्छ पेय जल , स्वास्थ्य सुविधाओ की उपलब्धता की सुनिश्चितता व स्थानीय भागीदारी से ही गांवो का सच्चा विकास संभव है. इन्हीं प्रयासों से गांवों का अस्तित्व बचा रहेगा और परोक्ष रूप से स्वतः ही गांवों से पलायन पर विराम लगेगा ।

ग्रामीण जीवन को बेहतर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्न बिंदुओं पर कार्य हों

1. रोजगार के अवसर बढ़ाना

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी पलायन का एक बड़ा कारण है। इसे रोकने के लिए:

- **छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग**: गांवों में छोटे उद्योग, जैसे हस्तशिल्प या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।
- **कृषि-आधारित व्यवसाय**: दूध, शहद, या जैविक खेती जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देना।
- **प्रशिक्षण केंद्र**: सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दे सकते हैं, ताकि वे स्थानीय स्तर पर रोजगार पा सके

2. कृषि को लाभकारी बनाना

कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इसके लाभकारी न होने से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसके लिए:

- **उचित मूल्य**: किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना।
- **आधुनिक तकनीक**: ड्रिप इरिगेशन, बीज सुधार, और जैविक खेती जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना।
- **बाजार पहुंच**: कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं के जरिए बाजार तक आसान पहुंच।
- **फसल बीमा और सब्सिडी**: प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई के लिए बीमा और सब्सिडी प्रदान करना।

3. शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं

शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी भी पलायन का कारण है। इसे बेहतर करने के लिए:

- **शिक्षा**: गांवों में गुणवत्तापूर्ण स्कूल और कॉलेज स्थापित करना, ताकि बच्चों को शहर न जाना पड़े।
- **स्वास्थ्य**: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों का विकास, जिससे लोग इलाज के लिए शहरों पर निर्भर न रहें।

4. बुनियादी ढांचे का विकास

ग्रामीण जीवन को आकर्षक बनाने के लिए मूलभूत सुविधाएं जरूरी हैं:

- **सड़क और परिवहन**: बेहतर सड़कें गांवों को बाजार और शहरों से जोड़ेंगी।
- **बिजली और पानी**: नियमित बिजली और स्वच्छ पानी की आपूर्ति।
- **इंटरनेट**: डिजिटल कनेक्टिविटी से लोग घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकेंगे।

5. स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा

ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए:

- **ऋण और मेंटरशिप**: छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ते ऋण और विशेषज्ञ मार्गदर्शन।
- **संभावित क्षेत्र**: हस्तशिल्प, जैविक खेती, या ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहन।

6. सामुदायिक भागीदारी

ग्रामीण विकास में समुदाय की भूमिका अहम है:

- **ग्राम पंचायतों को सशक्त करना**: स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाना।
- **जुड़ाव बढ़ाना**: लोगों को अपने गांव की प्रगति में भागीदार बनाना, जिससे उनका भावनात्मक लगाव बना रहे।

7. पर्यावरण और पर्यटन का विकास

गांवों की प्राकृतिक सुंदरता को आय का स्रोत बनाया जा सकता है:

- **ग्रामीण पर्यटन**: प्राकृतिक स्थलों, संस्कृति, और परंपराओं को बढ़ावा देकर पर्यटकों को आकर्षित करना।
- **हरित गांव**: पर्यावरण संरक्षण से गांवों को स्वच्छ और आकर्षक बनाना।

सहयोग की आवश्यकता

इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए **सरकार**, **गैर-सरकारी संगठन (NGO)**, और **ग्रामीण समुदाय** के बीच मजबूत सहयोग जरूरी है। सरकार नीतियां और संसाधन प्रदान कर सकती है, NGO तकनीकी सहायता और जागरूकता बढ़ा सकते हैं, और समुदाय स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन में योगदान दे सकता है।

स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे की जयंती 19 जुलाई पर विशेष.....

मंगल पांडे : भारतीय स्वाधीनता संग्राम के 'अग्रदूत'

प्रदीप कुमार वर्मा

'शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखरी निशां होगा...' मां भारती की आन,बान और शान की खातिर मर मिटने तथा उसे गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले शहीदों का अब यही फलसफा बाकी है। आज से करीब दो सौ साल पहले जन्मे महान स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे की आज जयंती है। शहीद मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक ऐसे अमर सेनानी के रूप में दर्ज है, जिसने ब्रिटिश फ़ौज में शामिल रहते हुए देशभक्ति का जज्बा बुलंद किया और यूनियन जैक के सामने एक चुनौती पेश की। महान शहीद मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया और सैन्य छावनी में ही कई अंग्रेज अफसर को मौत के घाट उतार दिया। मंगल पांडे के इस कदम से ब्रिटिश सेना भौचक्की रह गई और उन पर मुकदमा चला। इसके बाद उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन एक अमर सेनानी और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत के रूप में मंगल पांडे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।

गुलामी की वीडियो से मां भारती को आजाद कराने की लड़ाई में भागीदारी करने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को यूपी के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था। वर्ष 1849 में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए और बैरकपुर की सैनिक छावनी में बंगाल नेटिव इन्फैंट्री यानी बीएनआई की 34 वीं रेजीमेंट के पैदल सेना के सिपाही रहे। मंगल पांडे के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी एवं भारत विरोधी नीतियों के कारण अंग्रेजी हुकुमत के प्रति पहले ही नफरत थी। उस दौरान ब्रिटिश सेना की बंगाल यूनिट में ' पी.-53' राइफल आई। जिसमें कारतूसों को राइफल में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। उस जमाने में सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। ऐसे में हिन्दू और मुसलमानों में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के चलते दोनों धर्मों के सैनिकों के मन में अंग्रजों के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया।

फिर आई वह 9 फरवरी 1857 की तारीख, जब यह कारतूस पैदल सेना को बांटा गया। तब मंगल पांडेय ने उसे न लेने को लेकर विद्रोह के अपने इरादे जता दिए। इस बात से गुस्साए अंग्रेजी अफसर द्वारा मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतरवाने का आदेश दिया, जिसे मानने से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। आज़ादी की खातिर मर-मिटने का जज्बा दिल में लिए मंगल पांडे ने रायफल छीनने आगे बढ़ रहे अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण किया तथा उसे मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं उनके रास्ते में आए दूसरे एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग को भी मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह मंगल पांडे ने ब्रिटिश सेना की बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। यही वजह है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम की गाथा लिखने वाले इतिहासकार मंगल पांडे को आजादी की लड़ाई का ₹अगदूत₹ मानते हैं। भारतीय इतिहास में इस घटना को '1857 का गदर' नाम दिया गया है।

इस घटना के बाद मंगल पांडे को अंग्रेजी सेना के सिपाहियों ने गिरफ्तार किया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया और फांसी की सजा सुना दी गई। कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी। अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का अंदेशा था कि मंगल पांडे को फांसी की सजा दिए जाने वाले दिन कोई बड़ा विद्रोह और जनता में आक्रोश हो सकता है। इस बात को भांपते हुए अंग्रेजों द्वारा 10 दिन पूर्व ही यानि 8 अप्रैल सन 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस घटना ने भारतीय सैनिकों में असंतोष को और बढ़ाया और मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह की चिंगारी भड़की, जिससे पूरे उत्तर भारत में विद्रोह फैल गया। मंगल पांडे का बलिदान और विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने।

यौन हिंसा पर सख्त कानून के बावजूद आखिर अपराधों में कमी क्यों नहीं आ रही ?

हाल ही में ओडिशा के बालेश्वर जिले के एक कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यौन उत्पीड़न से परेशान होकर बी.एड की एक छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे राज्य में गुस्से और आक्रोश का माहौल है। यौन उत्पीडन की इस घटना के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय दल गठित कर दिया है, जो न केवल इसकी जांच करेगा बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जरूरी सुझाव भी देगा। पुलिस ने इस मामले में महाविद्यालय के प्राचार्य और विभागाध्यक्ष को हिरासत में ले लिया है। बहरहाल, यह बहुत ही दुखद और शर्मनाक है कि, जिस देश में नारी को शक्ति मानकर उसकी पूजा की जाती रही है, उस देश में आए दिन यौन उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार,हिंसा, महिलाओं पर अनर्गल और अश्लील टिप्पणियां जैसे अनेक मामले सामने आते हैं। यह सब दर्शाता है कि देश में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं।ताज़ा मामला जो सामने आया है उसके अनुसार बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा ने अपने कालेज के विभागाध्यक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न से त्रस्त होकर 12 जुलाई 2025 को खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह कर लिया था। मीडिया में आई खबरों से पता चलता है कि छात्रा कॉलेज के एक प्रोफेसर(शिक्षक) से परेशान थी और उसने कई बार उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इस संदर्भ में कोई ठोस व पुख्ता कदम नहीं उठाये। जानकारी के अनुसार छात्रा लगभग 95% जल चुकी थी और उसे पहले बालेश्वर अस्पताल और फिर एम्स भुवनेश्वर रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति ने इस मामले की जांच भी की थी। दरअसल , छात्रा ने प्रोफेसर के खिलाफ मानसिक और यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। यह भी जानकारी मिलती है कि प्रोफेसर छोटी-छोटी बातों पर छात्रों को क्लास से बाहर खड़ा कर देते थे।इसी प्रकार से एक बार वह छात्रा भी देर से आने पर क्लास से बाहर खड़ी कर दी गई थी, जिससे वह बहुत ही आहत हुई थी। मीडिया में आई खबरें बतातीं हैं कि प्रोफेसर ने छात्रा को सेमेस्टर परीक्षा देने से भी रोक दिया था और इसके अगले ही दिन छात्रा ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि प्रोफेसर ने छात्रा से 'फेवर' मांगने की बात कही थी। जब छात्रा ने पूछा कि कैसा फेवर, तो प्रोफेसर ने कथित रूप से कहा, 'तुम बच्ची नहीं हो, समझ सकती हो मैं क्या चाहता हूं।' इस मामले में आईसीसी (आंतरिक शिकायत समिति) ने संबंधित प्रोफेसर को हटाने की सिफारिश भी की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने समय रहते इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की और इसका असर यह हुआ कि पीड़ित छात्रा खुद को असहाय महसूस करने लगी और आखिरकार उसने आत्मदाह जैसा घातक कदम उठा लिया। इस घटना के बाद पूरे ओडिशा में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कई छात्र संगठन और विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रही हैं। कांग्रेस समेत अन्य सात विपक्षी दलों ने ने गुरुवार 17 जुलाई 2025 को पूरे राज्य में बंद का ऐलान भी किया, जिसका असर बाजार, स्कूल, कालेज पर देखने को मिला।

अब सवाल यह उठते हैं कि जब छात्रा ने शिकायत की थी, तो कार्रवाई में देरी क्यों हुई ? आईसीसी की सिफारिश के बावजूद आरोपी को क्यों नहीं हटाया गया? क्या कॉलेज प्रशासन छात्रा की जान बचा सकता था? कॉलेज की इस दुखद घटना ने न सिर्फ एक होनहार छात्रा की जान ले ली, बल्कि यह भी दिखा दिया कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में अगर समय पर कार्रवाई नहीं की जाए, तो इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या कॉलेज और प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेंगे या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा ? कितनी बड़ी बात है कि मीडिया में मामला उछलने और राजनेताओं की तल्ख प्रतिक्रिया के बाद प्राचार्य का निलंबन और आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी हो पायी है। जब पीड़ित छात्रा द्वारा कई प्लेटफॉर्म पर अपने यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई गई थी तो दोषी शिक्षक के खिलाफ समय रहते कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई? इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे ? जानकारी मिलती है कि छात्रा ने पहले प्राचार्य और फिर कालेज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी(आईसीसी) में भी शिकायत की थी। आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय छात्रा पर मामला रफा-दफा करने का दबाव बनाया गया। प्राचार्य को इस बात की चिंता थी कि मामला उजागर होने के बाद कॉलेज की बदनामी होगी। प्राचार्य को कॉलेज की बदनामी की चिंता थी, लेकिन छात्रा से कोई सरोकार नहीं, यह शर्मनाक है। सवाल यह है कि क्या महाविद्यालय की छवि, किसी छात्रा के जीवन से बढ़कर होती है ? पीड़िता ने इंसाफ के लिए हर उस दरवाजे पर दस्तक दी, जो उसे न्याय दिला सकता था, वह क्यों मौन साधे रहा? बताते यह भी हैं कि पीड़िता ने कई जन-प्रतिनिधियों से भी मामले की शिकायत की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी और छात्रा को आत्मदाह का विकल्प चुनने को मजबूर होना पड़ा।कॉलेज प्रशासन का इस मामले में गंभीरता और संवेदनशीलता नहीं दिखाना दर्शाता है कि कॉलेज प्रशासन को छात्र हितों से कोई सरोकार या वास्ता नहीं। ओडिशा में पिछले कुछ महीनों में यौन दुर्व्यवहार की कई घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। पाठकों को बताता चलूं कि कुछ समय पहले इसी साल एक इंस्टीट्यूट (वि.वि.) में पढ़ने वाली एक नेपाली छात्रा की मृत्यु हो गई थी। मृतका छात्रा नेपाल के बीरगंज की रहने वाली थी।उसका शव फंदे से लटका मिला। बालेश्वर वाली घटना के बारे में बताया जाता है कि छात्रा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स'(पहले ट्विटर)पर सार्वजनिक पोस्ट में न्याय की गुहार लगायी थी और चेताया था कि यदि मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वह अपनी जान दे देगी, लेकिन उसकी इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसे में उस छात्रा की मनःस्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि चारों ओर से निराश होने के बाद ही उसे ऐसा आत्मघाती कदम उठाया। सच तो यह है कि आज हमारे समाज में पाश्चात्य संस्कृति इस कदर हावी हो चुकी है कि हमारे सनातन मूल्यों, हमारी संस्कृति, हमारे आदर्शों, प्रतिमानों को भुला चुके हैं और आज हमारा नैतिक पतन होता चला जा रहा है। आज गुरू रक्षक नहीं भक्षक बन रहे हैं,यह बहुत ही दुखद है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना गया है, क्योंकि वे हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं।गुरु शब्द का अभिप्राय ही है-'अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला।' 'गिरति अज्ञानान्धकार मइति गुरुः' अर्थात इसका मतलब यह है कि जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञानरूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, वह गुरू है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आज गुरूओं में नैतिक मर्यादा, समाज और कानून का भय नहीं रह गया है। यहां सवाल यह भी है कि यौन हिंसा के मामले में सख्त कानून बन जाने के बावजूद इस तरह के अपराधों में कमी क्यों नहीं आ रही है ? सवाल यह भी है कि आखिर हमारे समाज की व्यवस्थाएं कब तक सुधरेगी ? कहना ग़लत नहीं होगा कि यह घटना वास्तव में परेशान करने वाली है। सीधे-सीधे यह हमारी व्यवस्थाओं पर कई तरह के सवाल खड़े करती है। हैरानी की बात है कि पीड़िता की मदद की बजाय इस मामले में चुप्पी साधी गई ? पाठकों को बताता चलूं कि निर्भया कांड अधिनियम, जिसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के रूप में भी जाना जाता है, 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के बाद पारित किया गया था। यह अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करता है, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों में। इसका उद्देश्य यौन अपराधों से संबंधित कानूनों को मजबूत करना और अपराधियों को कड़ी सजा देना है, लेकिन दुखद यह है कि इस अधिनियम के बावजूद भी पुलिस ने मामले में सक्रियता नहीं दिखाई। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज संस्थागत जिम्मेदारी और जवाबदेही भी निरंतर सवालों के घेरे में है।कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल महिला चिकित्सक के साथ, तथा इसके बाद लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ, दिल्ली में नौ वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन हमारे तंत्र ने इन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया,यह बहुत ही दुखद व शर्मनाक है। वास्तव में, हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2021 में महिलाओं के खिलाफ 428,278 अपराध दर्ज किए गए थे, जो 2011 की तुलना में 87% की वृद्धि है। इनमें से अधिकांश मामले घरेलू हिंसा, अपहरण, बलात्कार, दहेज हत्या और हमले से संबंधित थे। महिला उत्पीड़न से जुड़े इतने मामलों में बलात्कार के मामले में दोष सिद्धि मात्र 2.6 फीसदी ही है। कानूनी सुधारों के बाद भी बलात्कार के मामलों में सजा कम ही हो पा रही है।बलात्कार की परिभाषा को और व्यापक बनाने के लिए उसमें 'नॉन-पेनिट्रेटिव एक्ट' को भी शामिल किया गया है।इसके अलावा फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं और ऐसे अपराधों के लिए 16 साल से ऊपर के मुल्जिमों पर भी वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान भी लाया गया है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच बलात्कार के मामलों में दोष साबित होने की दर 27 से 28 प्रतिशत थी। आखिर महिलाओं के प्रति अपराध कब रूकेंगे और महिलाएं कब सुरक्षित होंगी। यौन उत्पीड़न व महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध वास्तव में तभी रूक सकते हैं,जब समाज में आमूलचूल बदलाव व जागरूकता आए।

सुनील कुमार महला

झारखंड का सबसे बड़ा औधोगिक जिले में पुनः मौत का तांडव सड़क पर

रात भर सैकड़ों गाडियां गुजरी शव के ऊपर, लोगों में आक्रोश

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची ,विकास के नाम पर औधोगीकरण की अंधी दौड़ का नमूना बना टाटा चाईबासा मार्ग के केसरगाडिया गांव के समीप बीती रात पुनः एक व्यक्ति बुरी तरह वाहनों से कुचल गया । एक्सीडेंट इतनी निर्ममता के साथ हुई की न जाने कितने ही वाहन उक्त व्यक्ति के शव को रौंदते हुए चलते बने । फिर क्या था वाहनों एक मानव शरीर के ऊपर से गुजरते देख लोग भड़क गये सड़क पर उतर कर सड़क को जाम कर दिया । जहां परिवहन सुरक्षा की धज्जियां उड़ाई जा रही थी लोग उसके गवाह बन रहे थे । यह माजरा स्थानीय औधौगिक परिवेश में काली कमाई का तूती बोलती है ।

सरायकेला खरसावां जिले के रूंगटा फैक्ट्री से राजनगर के बीच टाटा-चाईबासा मुख्य मार्ग पर स्थित केसरगाड़ियां मे बीती रात फिर एक व्यक्ति को निर्ममता से कुचल दिया गया ।जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।स्थानीय लोगों ने बताया कि रात भर कई मालवाहक गाड़ियां उस व्यक्ति के ऊपर से गुजरती रहीं। जिससे शव पूरी तरह से चिथड़े-चिथड़े हो गये । मृतक का अस्थिपंजर सबकुछ सड़क पर आटे की तरह गूंदा हुआ था । जब लोगों ने हादसे मे उक्त भयावह दृश्य को देखा तब ग्रामीण और अधिक आक्रोशित हो उठे । उन्होंने सड़क को जाम कर दिया, जिसके कारण टाटा-चाईबासा मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर राजनगर पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तब सड़क जाम कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर किसी तरह जाम हटाया।

राजनगर पुलिस ने शव के चिथड़ों को उठाने हेतु सरायकेला खरसावां पोस्टमार्टम हाउस से संपर्क कर लोगों को बुलाया। उसी क्रम में चाईबासा के लोगों को भी खबर हुई ।तब संबंधित मृतक परिवार घटना स्थल पर पहुंचे। जहां शव के चिथड़े-चिथड़े लगे कपडे आदि देख संतोष चौरोसिया नामक व्यक्ति के रूप में उसकी शिनाख्त हुई ।

सच तो यह है कि इस रूट पर औधौगिक क्षेत्र होने के कारण इलाके में मौत का तांडव आये दिनों सड़क पर नाचते नजर आता है ।सरकार ने उद्योग बसाकर मौत के मुंह में लोगों को डाल दिया है ।जब किसी इलाके औधौगिक विकास होता है तब व्यापारीगण परिवेश को ऐसे बना लेते कि यहां सरकार , मंत्री, अधिकारी, दलाल , पत्रकार सबका खाना -पानी रख दिया जाता। फिर वही आहिस्ता आहिस्ता सरकारी नियम अवरलुक होने लगता । वह इतना नीचे चला जाता कि सरकारी खजाने लुटने ज्ञान यहीं मिल जाता भ्रष्टाचारियों को । आज 1200 उद्योग से भरे इस जिला में आप अध्ययन कर सकते हैं । जमीन जिसने दिया मौत उसी का या तो उसके आंगन में !

परिवहन विभाग द्वारा दशकों से चली आ रही नियम में मालवाहक गाड़ियों से उगाही कर मोटी कमाई की जाती है इस औद्योगिक संपन्न जिले के विभिन्न सड़कों पर ।आज वही औधोगिक क्षेत्र लपेटो में लिए हुए है मानव व प्राणियों के जीवन को । परिवहन निगम का पालन नहीं होने के कारण ग्रामीण अपने ही माटी में आज सकते में हैं ।

झारखंड बार कौंसिल ने वकीलों को प्रमाणपत्र सत्यापन का दिया अन्तिम मौका

झारखंड बार में है 40 हजार वकील ,11009का हो चुका है सत्यापन

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , झारखंड बार कौंसिल ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को वकीलों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जल्द करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालयों को झारखंड बार कौंसिल ने पत्र भेजकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वकीलों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के लिए वकीलों के प्रमाणपत्र भेजे गए हैं, ऐसे दस्तावेजों का सत्यापन कर जल्द रिपोर्ट भेजने का आग्रह बार कौंसिल ने किया है, ताकि 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बार कौंसिल अपना पक्ष रखते हुए सही स्थिति की जानकारी दे सके। झारखंड में बार कौंसिल मे करीब 40 हजार वकील हैं

इनमें 11009 वकीलों का सत्यापन हो चुका है।7946 वकीलों ने सत्यापन का फॉर्म ही नहीं लिया था, शेष वकीलों के प्रमाणपत्रों की रिपोर्ट विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हो सकी है। जिन वकीलों ने प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए फॉर्म नहीं लिया था, उन्हें अंतिम मौका भी प्रदान किया गया है, जिसकी समय-सीमा भी बीत चुकी है। ऐसे 7946 वकीलों को 2000 रुपये फाइन के साथ फॉर्म लेकर भरने को कहा गया था। जानकारी के अनुसार, बार कौंसिल की नोटिस के बाद करीब 900 वकीलों ने फॉर्म लिया था। प्रमाण पत्र सही नहीं होने पर निबंधन होगा रद्द झारखंड बार कौंसिल सभी जिलों के बार संघों से जानकारी मंगाकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। जिन वकीलों के प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी और उनका निबंधन भी रद्द किया जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्र से प्रैक्टिस का सामने आया था मामला देश के कई कोर्ट में फर्जी प्रमाण पत्र के साथ प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का मामला प्रकाश में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों के प्रमाण पत्र और नियमित प्रैक्टिस का सत्यापन कराने का निर्देश बार कौंसिल ऑफ इंडिया को दिया है। इसके बाद से ही सभी बार कौंसिल को प्रमाणपत्रों का सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराने को कहा है। सत्यापन के बाद ही होंगे चुनाव झारखंड बार कौंसिल का कार्यकाल 28 जुलाई 2023 को समाप्त हो गया है। लेकिन, वकीलों के सत्यापन का काम पूरा नहीं होने पर कौंसिल की कार्यकारिणी को पहले छह माह का विस्तार दिया गया। बाद में 18 माह का अवधि विस्तार दिया गया, लेकिन सत्यापन का काम पूरा नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने देश के सभी बार कौंसिल को सत्यापन के बाद ही चुनाव कराने का निर्देश दिया है। सत्यापन में हो रहे विलंब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया

स्वच्छता के मामले में जमशेदपुर देश में तीसरा स्थान , राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

सरायकेला , झारखंड स्थित एकीकृत सिंहभूम जिले में 1907 में साकची नामक इलाके में स्थापित औधौगिक शहर जो कालांतर में अंग्रेजो द्वारा जमशेदपुर नाम से नामित हुआ, उक्त जिले को 3-10 लाख की आबादी में स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है . राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृहस्पतिवार को दिल्ली विज्ञान भवन में आवास एवं शहरी मामलों में एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण में 2024-25 का पुरस्कार प्रदान किया .

इस मौके पर राष्ट्रपति ने प्रधान सचिव-नगर विकास एवं आवास विभाग सुनील कुमार, निदेशक- सुडा सूरज कुमार एवं अपर नगर आयुक्त-जेएनएसी कृष्ण कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया. गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार के लिए झारखंड से जमशेदपुर को नामित किया गया था. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया.

जमशेदपुर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इस उपलब्धि पर भी सफाई कर्मियों, जागरूक शहर वासियों एवं नगरीय निकाय प्रशासन को बधाई दिया. उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, "यह पूरे जिले के लिए गौरव का क्षण है, जहां राष्ट्र स्तर पर जमशेदपुर को स्वच्छता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया. यह सम्मान शहरवासियों की जागरूकता, निगम कर्मियों की निरंतर मेहनत और प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम है. हम सभी को इसी तरह मिलकर स्वच्छता को अपनी आदत और संस्कृति बनाना होगा.

एक शाम श्री श्री 1008 संत श्री देवाराम जी महाराज की 31 वी बरसीं पर जागरण सम्पन्न

हैदराबाद उप्पल : चंगीचैरला स्थित कुमावत सेवा समिति उप्पल चंगीचैरला के तत्वावधान में श्री श्री 1008 संत श्री देवाराम जी महाराज की 31 वी बरसीं पर पूजा अर्चना व भजन प्रस्तुत किये । इस अवसर पर उपस्थित संरक्षक चन्द्र प्रकाश मोटावत, अध्यक्ष बाबूलाल खरनालिया ,सचिव नाथूराम लारना, उपाधयक्ष ओमप्रकाश पीपाड़ा, रमेश कुमार हावलेचा ,श्रवण कुमार बाकरेचा , सदस्य नाथूराम बावलिया, ओमप्रकाश मोटावत , ओमकार दुबलदिया, गणपत बावलेचा धाराराम रेणवाल ,रमेश कुमार अडाणिया समाज बन्धु व अन्य ।

न्यायिक विभागीय जाँच होने तक आंदोलन जारी रहेगा। : संयुक्त विपक्ष

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भुवनेश्वर : कांग्रेस समेत आठ विपक्षी राजनीतिक दलों ने ओडिशा बंद को सफल बनाने के लिए राज्य की जनता का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। संयुक्त विपक्षी दल ने कहा कि वे राज्य की जनता, वामपंथी और लोकतांत्रिक दलों, ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों, वकीलों, व्यापारिक संगठनों और समाज के सभी वर्गों का इस बंद को पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। राज्य की जनता के पूर्ण सहयोग से ही यह बंद सफल रहा। संयुक्त विपक्षी दल ने कहा कि यह बंद अब जनता का बंद बन गया है। फकीर मोहन महाविद्यालय की छात्रा की सुनियोजित हत्या की न्यायिक जाँच की माँग के साथ-साथ, डबल इंजन वाली भाजपा सरकार के कुशासन, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की उपेक्षा और राज्य में कानून-व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति के विरुद्ध इस बंद का आह्वान किया गया था। बाजार, परिवहन, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय, बैंक और बीमा जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पूरी तरह बंद रहे। हालाँकि, आवश्यक सेवाओं, एम्बुलेंस और चिकित्सा सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया।

फकीर मोहन कॉलेज में छात्र की मौत की घटना की न्यायिक जाँच, उच्च शिक्षा मंत्री, बालासोर के सांसद और बालासोर के विधायक के इस्तीफे की माँग की गई। साथ ही, बालासोर के जिलाधिकारी और सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की माँग की गई। संयुक्त विपक्षी दल ने कहा है कि मोहन माझी ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

आज के बंद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास, ओडिशा प्रभारी अजय लालू, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला संघ की अध्यक्ष अलका आदि, कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचन्द्र कदम, निरंजन पटनायक, जयदेव जेना, रामचन्द्र खुंटिया, श्रीकांत जेना, जगन्नाथ पटनायक, अमर प्रधान, विधायक रेमेश जेना, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीनाक्षी बाहिनीपति, सेवा दल अध्यक्ष सुभेंदु मोहंती, उपाध्यक्ष देबाशीष पटनायक, भुवनेश्वर जिला समन्वयक विश्वजीत दास, जानकी शामिल हैं। बल्लव पटनायक, सुब्रत महापात्र, सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव रामकृष्ण पांडा, राज्य सचिव आशीष कानूनगो, सीपीआई (एम) के राज्य सचिव सुरेश चंद्र पाणिग्रही, राज्य सचिव संघम सदस्य विष्णु मोहंती, सीपीआई (एमएल)-लिबरेशन के राज्य सचिव युधिष्ठिर महापात्र, पूर्व विधायक राधाकांत सेठी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राज्य महासचिव ज्योति रंजन महापात्र, लक्ष्मी डोरा, एनसीपी के राज्य अध्यक्ष विक्रम स्वैन, सपा के राज्य महासचिव प्रताप बारिक, विजय बेहरा, राजद के प्रदेश महासचिव हेमंत कुमार, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवानंद रे, रजनी मोहंती, अरविंद दास, अशोक दास, प्रशांत चंपति, प्रकाश जेना, प्राची राउतराय, अनवर खान, सचिव तकवियाम, मिहिर आचार्य, पार्वती प्रताप सिंह, आशीष मल्लिक, विनोदराज जेना, दीपक साहू, देबाशीष राउत, अक्षय कुमार दास, सैमेंद्र मोहंती, मंटू मल्लिक, मनोज साहू, अनिल दास, श्रेया मोहंती, प्रसन्न नायक, देबब्रत मोहंती, लल्लोएटंडु दास, मित्रभानु महापात्र, संकुना कनार, देबाशीष महापात्र, प्रमेश साहू, कृष्णचंद्र पति, आत्माराम पति, नारायण जेना, निहार महापात्र, मनरंजन जेना ने राज्य स्तरीय बंद का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। पुलिस ने आंदोलन में हिस्सा लेने के आरोप में सैकड़ों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और रिजर्व पुलिस लाइन कार्यालय ले गयी. संयुक्त विपक्ष ने फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा की मौत की न्यायिक जाँच, महिला सुरक्षा और राज्य में कानून का राज स्थापित करने की माँग को लेकर मुद्दा आधारित आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। राज्य की जनता की एकता और सहयोग से सक्रिय भागीदारी के कारण बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण और असाधारण रूप से सफल रहा है। संयुक्त विपक्ष ने पूरे राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है।

ट्रेन का इंतजार कर रहा बिहार का तस्कर 3 किलो 900 ग्राम चरस के साथ कानपुर में गिरफ्तार

सुनील बाजपेई

कानपुर। अपने घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे बिहार के रहने वाले शातिर तस्कर को लाखों रुपए कीमत की 3 किलो 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

जीआरपी और आर पी एफ को यह सफलता

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मिली। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के सरैया नवादा गांव के रहने तस्कर 22 साल के तूफान महतो के पास से 3 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई है। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है।

जीआरपी ने बताया कि उसे हैरिस गंज पुल के पास से उसे पकड़ा गया। उस समय वह पीपल के पेड़ के नीचे बिहार जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था।

तस्कर की गिरफ्तारी के विवरण में यह भी बताया गया कि यह कार्रवाई एडीजी रेलवे प्रकाश डी के मार्गदर्शन में एसपी रेलवे प्रयागराज प्रशांत वर्मा की निगरानी में टीम ने यह सफलता हासिल की। डीएसपी कानपुर दुष्यंत कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जीआरपी कानपुर सेंट्रल के प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह और आरपीएफ पोस्ट प्रभारी सिद्धनाथ पाटीदार भी शामिल थे।

ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कुछ ट्रेनों के समय में विस्तार किया है तथा कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े हैं

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वरः यात्रियों की सुविधा के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कुछ ट्रेनों के समय में विस्तार किया है और कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। इस संबंध में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जानकारी दी है। भुवनेश्वर-धनबाद स्पेशल ट्रेन का समय 31 जुलाई तक और भुवनेश्वर-धनबाद स्पेशल ट्रेन का समय 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।शालीमार-पुरी स्पेशल में 31 अगस्त से और शालीमार से पुरी के बीच 1 सितंबर से अतिरिक्त कोच बढ़ाए गए हैं। सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोच से बढ़ाकर 20 कोच कर दिए गए हैं। राउरकेला-गुनुपुर-राउरकेला राज्य रानी एक्सप्रेस में एक स्लीपर क्लास कोच और एक एसी 2 टियर अतिरिक्त कोच जोड़ा गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**